

# जगत विज्ञान

पिछले एक साल में कम हुई  
नक्सली घटनाएं



छत्तीसगढ़ और केन्द्र सरकार के साझा  
प्रयासों से नक्सली लौट रहे मुख्य धारा में



प्रेरणा स्रोत : स्व. श्री जगत पाठक



निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक  
कार्यकारी संपादक समता पाठक  
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय  
भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल  
मो. 98260-64596, मो. 9893014600  
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स  
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज  
एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लॉट नं. 28 सुरभि विहार  
बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17,  
शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया  
पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय  
रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख  
एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका

वर्ष 25 अंक 03 नवम्बर 2024

# पिछले एक साल में कम हुई नक्सली घटनाएं

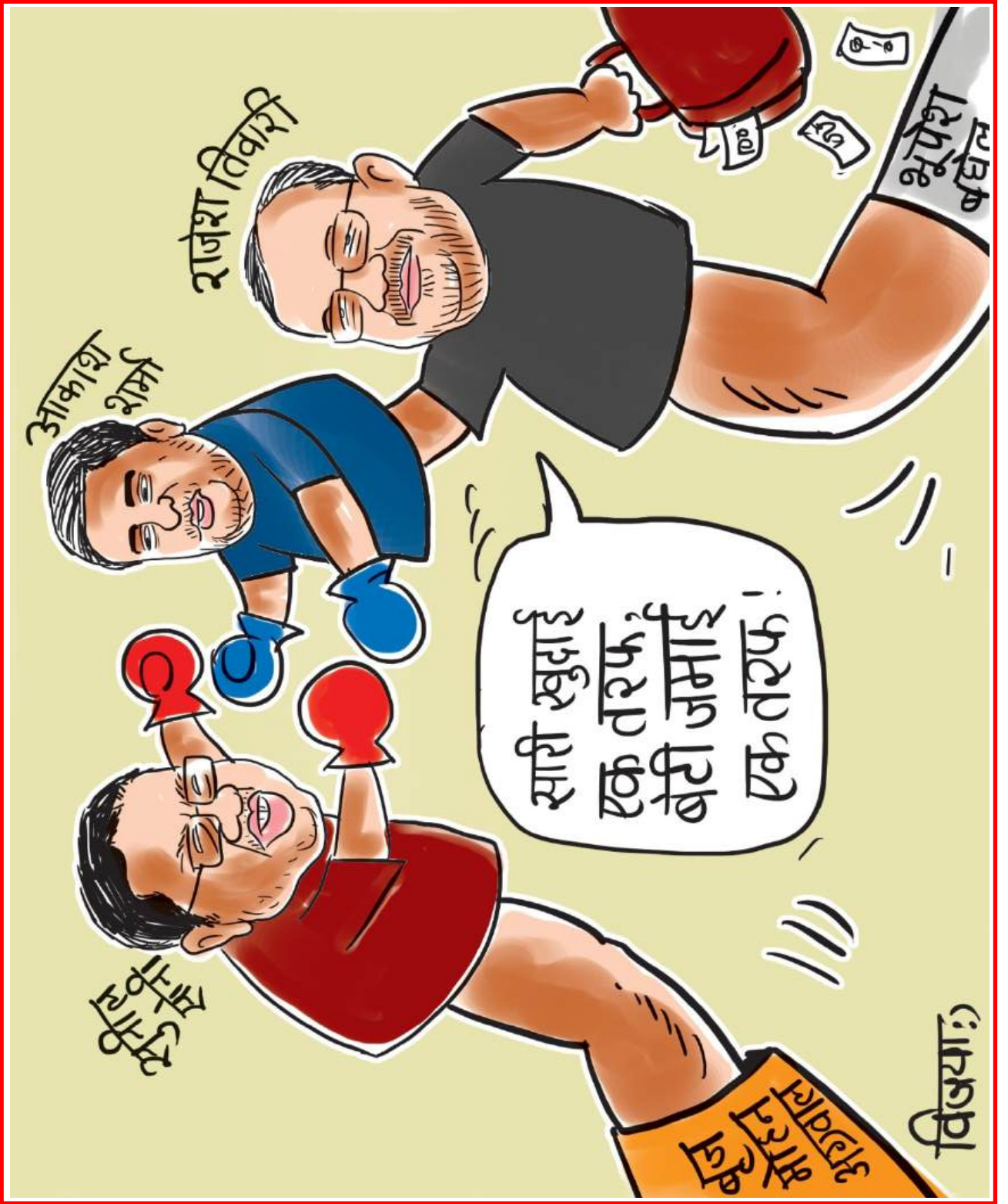


छत्तीसगढ़ और केन्द्र सरकार के झगड़ा  
प्रयासों से नक्सली लौट रहे मुख्य धारा में

(पृष्ठ क्र.-6)

- महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा मध्यप्रदेश .....23
- कर्ज के दलदल में डूब रहा है मध्यप्रदेश के नौजवानों का भविष्य .....32
- ट्रंप की जीत के भारत के लिए मायने .....37
- स्वाधीनता संग्राम के प्रखर और कर्मठ नेता थे पं. नारायणराव मेघावाले .....42
- हाथी और मानव के बीच बढ़ा संघर्ष .....44
- आबादी के आंकड़ों की छिपी कहानी .....48
- भारत आज लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और डाटा के मजबूत स्तंभों पर खड़ा है ..53
- महाराष्ट्र और झारखंड के विस चुनाव में दांव पर लगी पार्टियों की साख .....56
- How many economists have seen the inside of a factory? .....61





## ट्रंप से भारत के मधुर संबंधों का कितना फायदा

डोनाल्ड ट्रंप और नरेन्द्र मोदी के संबंध हमेशा मधुर रहे हैं। अब ट्रंप की नई पारी में भारत और अमेरिका एक बार फिर नजदीक आ गये हैं। ट्रंप और मोदी, दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त बताते हैं। ट्रंप सरकार के फैसले भी भारत के लिए मुफीद बैठे हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है कि ट्रंप की जीत का वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ेगा और इससे भारत अमेरिका के रिश्तों को कितनी मजबूती मिलेगी। दरअसल, अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत में खुशी भी है, उम्मीद भी। क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों के चार बड़े स्तंभ हैं। ट्रंप का कार्यकाल हमारा देश देख चुका है। कहा गया कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्त रहे हैं और उनका जीतना भारत के लिए बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के संबंध अमेरिका के दोनों दलों के प्रमुख नेताओं के साथ अच्छे रहे हैं। अगर कमला हैरिस जीतती तो उनके साथ भी उनके संबंध बेहतर हो जाते। मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रंप ने उद्योगपति के रूप में काम किया है, उसका असर उनके कार्यकाल में दिखाई देगा। पहले कार्यकाल की तुलना में उनका दूसरा कार्यकाल काफी बेहतर और परिपक्व होगा। भारत के कनाडा से बिगड़े रिश्तों से लेकर दुनिया में चल रहे युद्धों पर उनकी भूमिका देखने वाली होगी।

डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुना जाना एक महत्वपूर्ण वैश्विक घटना है। यह चुनाव न केवल वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेगा, बल्कि कई आर्थिक बदलावों का भी कारण बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप द्वारा लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों के प्रभाव को समझने के लिए उनके पहले कार्यकाल पर दृष्टि डालना आवश्यक है। यह वह समय था जब ट्रंप को 'टैरिफ किंग' के रूप में जाना गया। इस दौरान विशेष रूप से उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रति ट्रंप का दृष्टिकोण अधिक सख्त था। ट्रंप की आर्थिक सोच के अनुसार, कुछ विकासशील देश, विशेषकर चीन, अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए अनेक रियायतें प्राप्त करते हैं। ये देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुल्क में छूट हासिल करते हैं। इसी कारण से ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर अधिक शुल्क (टैरिफ) लगाना शुरू किया था, जिसे आर्थिक भाषा में 'व्यापार संरक्षणवाद' कहा जाता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन ने सोलर पैनल, वॉशिंग मशीन, स्टील, एल्यूमीनियम और चीन से आयातित कई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप, 2019 में टैरिफ से 79 बिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि थी। यह एक व्यापार युद्ध के रूप में उभर कर सामने आया, जिसमें दुनिया के दो ताकतवर राष्ट्र आपस में टकरा रहे थे।

व्यापार युद्ध वह स्थिति है जब देश एक-दूसरे के व्यापार पर अतिरिक्त और कोटा लगाकर आर्थिक प्रहार करते हैं। इसमें एक देश अपनी स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाता है। इसके प्रत्युत्तर में दूसरा देश भी इसी प्रकार के करों को बढ़ाकर प्रतिक्रिया देता है, जिससे 'जैसे को तैसा' की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार का व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार में अवरोध उत्पन्न करता है, और अन्य अर्थव्यवस्थाओं को भी क्षति पहुंचता है।

अब वर्तमान पर बात करें तो, ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान वादा किया था कि वह अमेरिका की बेरोजगारी, महंगाई और अन्य आर्थिक चिंताओं को दूर करेंगे। इसके लिए वह बहुत से नीतिगत बदलाव करेंगे, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय हित में भी विचार किया जाना चाहिए। पहला, क्या ट्रंप एक बार फिर व्यापार युद्ध की राह पर चलेंगे? यदि वे चीन के साथ ऐसा करते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वे भारत पर भी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाएंगे? दूसरा, ट्रंप ने घरेलू रोजगार बढ़ाने के लिए उत्पादन इकाइयों को वापस अमेरिका लाने का एलान किया है, यानी विदेश में सस्ती वस्तुएं और श्रम से उत्पादन कर रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाने का प्रयास किया जाएगा।

विजया पाठक

# पिछले एक साल में कम हुई नक्सली घटनाएं



**छत्तीसगढ़ और केन्द्र सरकार के साझा  
प्रयासों से नक्सली लौट रहे मुख्य धारा में**

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। विभाजित छत्तीसगढ़ और अविभाजित छत्तीसगढ़ दोनों की समय नक्सलवाद ने प्रदेश को घेरे रखा है। 2000 में राज्य के गठन के बाद प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो हर एक सरकार को नक्सलवाद से लड़ना पड़ा है। सरकार भले ही बदलती रहीं हों लेकिन नक्सलवाद अपने चरम पर रहा। सरकारों ने नीतियां बनाई, कई प्रयोजन किये लेकिन यह समस्या जस की तस बनी रही। वर्तमान में प्रदेश में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है। इस सरकार के आने के बाद राज्य से नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद जगी है। साय सरकार की नीतियों और प्रयासों से काफी हद तक नक्सलवाद के दंश से राहत मिलती दिख रही है। 2016 में 134 नक्सलियों को डेर किया गया था। यह संख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने लगभग 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं 801 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 742 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। नक्सलियों को डेर करने के पीछे का बड़ा राज यह है कि राज्य की पुलिस और केंद्रीय बल आपस में बेहतर तालमेल बैठ पा रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में नक्सली इलाकों में कैंप भी खोले गए हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार के राज में पांच साल में कुल 210 नक्सली को डेर किए गए हैं। वहीं साय सरकार में यह आंकड़ा काफी बड़ा है। राज्य की जनता को सुकून और खुशहाली देने के लिये प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल मुक्त राज्य बनाने का पहले तो संकल्प लिया और उसके बाद लगातार राज्य को सिलसिलेवार ढंग से चलाये जा रहे योजनाबद्ध अभियानों से नक्सलियों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नक्सलियों के आतंक की समाप्ति का यह अभियान अभी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा चुनाव के पहले से शुरू कर दिया था। पुरानी सरकार की तुलना में वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने एक साल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। बीते छह महीनों में सबसे ज्यादा एनकाउंटर और नक्सलियों के सरेंडर हुए। बड़ी संख्या में नक्सलवादियों की गिरफ्तारी भी नई सरकार के कार्यकाल में हुई। नक्सलवाद के खात्मे के लिए ग्रामीणों का भरोसा जीतने की भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। नए-नए अभियान लॉन्च किए जा रहे हैं। पिछले पांच साल और अभी के 6-7 महीने में बड़ा अंतर फोर्स के एक्शन में नजर आया। नई सरकार आने के बाद नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादियों के आत्म समर्पण से जुड़ी नई योजना लागू भी लागू की है जिसके अंतर्गत प्रदेश में इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

### विजया पाठक

किसी भी राज्य में खुशहाली और समृद्धि तब तक संभव नहीं है जब तक वहां

भय मुक्ति का वातावरण न बनाया जाये। फिर वह भय भले ही नक्सलियों का क्यों न हो। छत्तीसगढ़ में वर्षों से नक्सलियों ने राज्य

की जनता का सुख-चैन छीना है। ऐसे में राज्य की जनता को सुकून और खुशहाली देने के लिये प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री विष्णुदेव



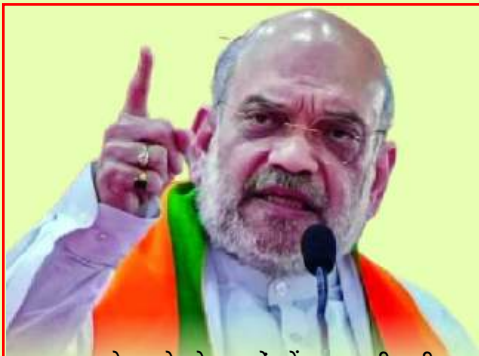
## खुशहाल गांव और खुशहाल गांववासी

नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ने से गांव और गांववासी खुशहाल नज़र आ रहे हैं।  
उनमें भी शांति और विकास की आस जागृत हुई है।

साय ने नक्सल मुक्त राज्य बनाने का पहले तो संकल्प लिया और उसके बाद लगातार राज्य को सिलसिलेवार ढंग से चलाये जा रहे योजनाबद्ध अभियानों से नक्सलियों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नक्सलियों के आतंक की समाप्ति का यह अभियान अभी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा चुनाव के पहले से शुरू कर दिया था। उन्हीं के नेतृत्व में राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सरकार ने यह साबित भी किया है। यह संकल्प ऐसे समय में और

**साय सरकार में  
हल होती दिख  
रही नक्सलवाद  
की समस्या**

भी महत्व रखता है, जब सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने को लेकर गंभीर है। नक्सली समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ की साय सरकार समानांतर रणनीति के तहत काम कर रही है। सरकार की नई रणनीति का ग्राउंड लेवल पर बड़ा असर भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कितने वक्त में ये समस्या खत्म हो जाएगी कहना मुश्किल है। पर इतना जरूर है कि इस समस्या का अंत सामाजिक सहभागिता से जल्द हो सकता



## नक्सलवाद दो साल से ज्यादा नहीं टिकेगा

आने वाले दो सालों में नक्सली पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आतंक के अंत को लेकर सालों से हर सरकार अपने अपने दावे कर रही है। बीजेपी की सरकार में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार नक्सलवाद के अंत के लिए नई रणनीति के तहत काम भी कर रही है। एक दो घटनाओं को छोड़ दें तो नक्सली संगठन पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो लड़ाई को रफ्तार पकड़ने में थोड़ा टाइम लग गया था। अब हम वहां पर पहुंच गए हैं, जहां पांच ही महीनों के अंदर 125 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 350 ने सरेंडर कर दिया है और 250 को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सलवाद दो साल से ज्यादा नहीं टिकेगा।

**अमित शाह, केन्द्रीय गृहमंत्री**

है। सरकार का दावा है कि पूर्ववर्ती सरकार के 05 साल में नक्सलियों के खिलाफ इतनी तेज कार्रवाई नहीं की गई। पुरानी

सरकार की तुलना में वर्तमान भाजपा सरकार ने अपने एक साल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। बीते छह महीनों

में सबसे ज्यादा एनकाउंटर और सरेंडर नक्सलियों के हुए। बड़ी संख्या में नक्सलवादियों की गिरफ्तारी भी नई सरकार

## नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है

नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी, इसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। पहले 10 वर्षों में 6617 सुरक्षाकर्मी और नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अब इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है और हम देश को मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं का 100 फीसदी क्रियान्वयन हो, ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति हो और ऐसी परियोजनाओं के दौरान आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए।



**विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़**



# बस्तर में दम तोड़ता नक्सलवाद

छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद यह पहला अवसर है जब सुरक्षाबलों की तैयारी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब बस्तर संभाग में नक्सलवाद की लौ बुझने की ओर है। बस्तर संभाग के कुछ हिस्से अब भी नक्सलवाद की बची-खुची साख को कवच प्रदान कर रहे हैं। यहां नक्सलियों का किला अब लगभग ध्वस्त हो चला है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के लिए बीते पांच वर्ष सुकून के रहे, क्योंकि न बड़े अभियान चले और न ही बड़े स्तर पर घेराबंदी हुई। राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार बनते ही बस्तर में नक्सल रणनीति आश्चर्यजनक रूप से बदल गई। अचानक नक्सल हमले तेजी



से बढ़े और संभाग के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षाबलों को लक्षित कर लगातार हमले होने लगे। राज्य सरकार ने भी सक्रियता दिखाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही अनेक बार यह प्रतिबद्धता दर्शा चुके हैं कि नक्सलवाद को बस्तर से ही नहीं, देश से समाप्त करना है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सरकार और सुरक्षाबलों की सक्रियता दो स्तरों पर दिखी। पहला लगातार शिविर बना कर क्षेत्र में अभियान चलाए गए और सूचना आधारित लक्षित हमलों में तेजी लाई गई। शुरू में सरकार पर दबाव देखा जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि नक्सली परेशानी में हैं, उनकी कमर टूट रही है। कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में बिनागुंडा एवं कोरोनार के मध्य हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की टीम ने नक्सलियों को घेरकर बड़ी संख्या नक्सलियों को मार गिराया। यह कार्रवाई सटीक खुफिया सूचना के आधार पर की गई। यही कारण है कि सुरक्षाबल इस आमने-सामने की लड़ाई में नक्सलियों पर हावी दिखे। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। आमतौर पर नक्सली अपने साथियों के शव साथ ले जाने में सफल रहते हैं। इसलिए हताहत नक्सलियों की संख्या का सही अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाता था, परंतु इस बार परिस्थिति अलग थी। सुरक्षाबल योजना और तैयारी में नक्सलियों पर भारी पड़े। इसीलिए न केवल अभियान

के कार्यकाल में हुई। नक्सलवाद के खात्मे के लिए ग्रामीणों का भरोसा जीतने की भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। नए-नए

अभियान लॉन्च किए जा रहे हैं। पिछले पांच साल और अभी के 6-7 महीने में बड़ा अंतर फोर्स के एक्शन में नजर आया। नई सरकार

आने के बाद नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर रही है। नई रणनीतियों को लेकर आगे बढ़ रही

सफल रहा, अपितु सभी 29 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। कांकेर में मिली सफलता इकलौती नहीं है। हाल के दिनों में बस्तर संभाग के दक्षिणी छोर में स्थित कोरचोली और लेंड्रा के जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सली अब समझ रहे हैं कि बस्तर से उनके बाहर जाने का समय आ गया है। राज्य और केंद्र सरकार के एक ही पृष्ठ पर आ जाने के कारण क्षेत्र में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल रही हैं। सजगता का उदाहरण है कि केंद्रीय गृहमंत्री ने 22 जनवरी 2024 को रायपुर में बैठक कर नक्सलवाद की समाप्ति के लिए तीन वर्ष की समय सीमा तय की थी।

#### 40 सालों से चल रहा है बस्तर में संघर्ष

सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच पिछले 40 सालों से बस्तर के इलाके में संघर्ष चल रहा है। राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ में 3200 से अधिक मुठभेड़ की घटनाएँ हुई हैं। गृह विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2001 से मई 2019 तक माओवादी हिंसा में 1002 माओवादी और 1234 सुरक्षाबलों के जवान मारे गये हैं। इसके अलावा 1782 आम नागरिक माओवादी हिंसा के शिकार हुए हैं। इस दौरान 3896 माओवादियों ने समर्पण भी किया है। 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि 30 नवंबर तक राज्य में 31 माओवादी पुलिस मुठभेड़ में मारे गये थे, वहीं 270 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। माओवादी मुठभेड़ और आत्मसमर्पण की खबरों के बीच-बीच में शांति वार्ता की पेशकश की चिड़्डी और विज्ञप्तियां भी आती-जाती रहती हैं लेकिन बात कहीं पहुंचती नहीं है। माओवादियों ने सुरक्षाबलों को बस्तर से हटाने, कैंपों को बंद करने और माओवादी नेताओं को रिहा करने की मांग के साथ शांति वार्ता के लिए कहा था। सरकार ने इस पेशकश को यह कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया था कि शर्तों के साथ बात नहीं होगी और माओवादी पहले हथियार छोड़ें, फिर बातचीत की बात करें। बस्तर में आदिवासियों के कानूनी पहलू पर काम करने वाली अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला का कहना है कि हथियार कोई भी नहीं छोड़ना चाहता।

#### नक्सलवाद पर आखिरी वार की तैयारी! CRPF ने 4,000 से ज्यादा जवान भेजे छत्तीसगढ़

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) छत्तीसगढ़ के बस्तर के सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4,000 से अधिक कर्मियों वाली चार बटालियनों को तैनात कर रहा है। ये मार्च 2026 तक माओवादी समस्या को खत्म करने के केंद्र सरकार के नए संकल्प के तौर पर एक निर्णायक लड़ाई शुरू करने की रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने झारखंड से तीन और बिहार से एक बटालियन को वापस बुलाया है। इनकी तैनाती प्रदेश की राजधानी रायपुर से करीब 450 से 500 किलोमीटर दक्षिण स्थित बस्तर क्षेत्र में की जायेगी। बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को देश में प्रमुख आंतरिक सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियान बल के तौर पर जाना जाता है।



है। सरकार सरेंडर और खात्मे के दोनों रास्तों पर आगे बढ़ रही है। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। नक्सलियों को

सरकार घेराबंदी भी कर रही है और समर्पण की नीति पर भी आगे बढ़ रही है। समर्पण नीति के तहत अब सरेंडर करने वाले

नक्सली जहां चाहें वहां पुनर्वास कर सकते हैं। उनको आजीवका का साधन भी मुहैया कराया जाएगा। पहले की पुनर्वास नीति को

# नक्सलियों का खूनी खेल



दंतेवाड़ा नक्सली हमला 2005

इस बीच लगभग संपूर्ण बस्तर क्षेत्र में हत्याएं रोज-मर्रा की बात हो गईं। 2005 में दंतेवाड़ा के एराबोर क्षेत्र में नक्सली हमले में 30 पुलिसकर्मी बलिदान हो गए। इसी तरह, जुलाई 2006 में एराबोर के सलवा जुड़ूम जुड़ूम शिविर पर नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों ने लगभग 500 झोपड़ियों में आग लगा दी थी, जिसमें 37 वनवासी मारे गए और सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए थे। 2007 में नक्सलियों ने बीजापुर जिले के रानीबोदली पुलिस पोस्ट पर हमला कर 55 सुरक्षाकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर जुलाई 2009 में राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र मदनपाड़ा गांव, खोड़ेगांव और कारकोटी के मध्य जंगल में पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सहित 39 पुलिसकर्मी बलिदान हो गए। अब तक का सबसे बड़ा हमला 06 अप्रैल 2010 की सुबह के छह बजे हुआ। सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के

सरकार ने बदल दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सली चाहें तो अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं या फिर उनको अपने साथ रख

सकते हैं। रोजगार के लिए कम दरों पर लोन भी उनको मुहैया कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद

नक्सलियों को घेरने के लिए सुरक्षाबलों ने नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। सरकार एक तरह सरेंडर की

संयुक्त दल में शामिल लगभग सौ सुरक्षाकर्मी सड़क खोलने का काम पूरा कर लौट रहे थे। जब वे तारमेटला और चिंतलनार गांव के बीच जंगलों से होकर गुजरे तो नक्सलियों ने विस्फोट कर उनके वाहन को उड़ा दिया और जवानों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस घटना में सीआरपीएफ के 76 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। 25 मई 2013 की घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज है। जगदलपुर से 47 किलोमीटर दूर दरभा के झीरमघाट में माओवादियों ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सुकमा से जगदलपुर लौट रही कांग्रेस पार्टी के एक समूह पर दरभाघाटी में दो पहाड़ों के बीच हमला, जहां से किसी के लिए भी जान बचा कर भागना संभव नहीं था। बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद फायरिंग में पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, राजनांदागांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार और स्थानीय नेता गोपी माधवानी सहित 29 लोगों की की मौत हो गई। इसके अलावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल की भी नक्सलियों ने हत्या कर दी। बुरी तरह घायल वयोवृद्ध नेता विद्याचरण शुक्ल का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हुआ। महेंद्र कर्मा को नक्सलियों ने न केवल बेरहमी से मारा, अपितु उनके शव पर नाच-कूद कर विजय जश्न मनाते रहे। इस हमले में नक्सलियों का क्रूरतम पैशाचिक चेहरा दिखा। लेकिन यह अंत नहीं था। यहां केवल प्रमुख घटनाओं को सूचीबद्ध किया गया है। ऐसी अनेक घटनाएँ हैं, जैसे- अप्रैल 2017 को सुकमा में हमला हुआ, जिसमें 25 जवान बलिदान हुए थे। सुकमा में ही 2018 में आईईडी विस्फोट में सात जवान बलिदान हुए थे। अप्रैल 2021 को बीजापुर और सुकमा की सीमा पर घात में फंसकर 22 जवानों की जान गई थी। अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में दस जवानों की जान चली गई



बीजापुर नक्सली हमला 2007



सुकमा नक्सली हमला 2018

पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर सरकार एनकाउंटर के जरिए नक्सलियों में खौफ पैदा कर रही है। सरकार की इस नई

रणनीति से नक्सली बैकफुट पर आ चुके हैं। सरेंडर और एनकाउंटर की ज्वाइंट रणनीति से आतंक के खिलाफ नया

चक्रव्यूह तैयार किया गया है।

जब कोई सरकार या सत्ता यह ठान ले की वो अराजकता को जड़ से नष्ट करके ही

थी। कहने का अर्थ यह है कि नक्सली अब भी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यह भी तथ्य है कि बस्तर संभाग से नक्सलवाद की लौ फड़फड़ा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के अद्भुत तालमेल और सुरक्षा एजेंसियों के वैशिष्ट्य समन्वय से निश्चित ही छत्तीसगढ़ जल्दी नक्सल मुक्त होगा। इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि जमीनी स्तर पर नक्सलियों द्वारा जो क्रूरता की जाती है, उसे शहरी नक्सलियों द्वारा सही ठहराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती है। खून-खराबे और मध्ययुगीन बर्बरताओं को व्रंतिकारी जोश और जुनून जैसी लफ्फाजियों से लीपापोता जाता है और ऐसा करते हुए मानवाधिकार जैसी अवधारणाओं की धज्जियां

उड़ाकर रख दी जाती हैं। किसी निरीह ग्रामीण, आदिवासी, सरपंच, पटेल या शिक्षक को मुखबिर या वर्ग निरूपित कर आहिस्ता-आहिस्ता गला काटने वाले यही नृशंस लोग अपने उपर होने वाली किसी भी कार्रवाई का सामना शहरी नक्सलवादियों द्वारा बुनी गई मानव-अधिकार की ढाल से ही करते हैं। पुलिस, अर्धसैनिक बल अथवा सेना की प्रत्येक कार्रवाई पर प्रश्न खड़ा करने का इनका यही तौर तरीका है। वे सच्ची-झूठी, सत्यापित-असत्यापित, किसी भी घटना को वैश्विक बनाने की क्षमता रखते हैं। शहरी नक्सल तंत्र इतना संगठित कार्य करता है कि देश केवल उनकी परोसी-गढ़ी खबरों पर ही चर्चा करता है। इसी बार देखिए, बस्तर देश का ऐसा इलाका है जहां रोज निर्मम और क्रूरतम तरीके से हत्या की जाती है, लेकिन मारे जाने वालों के अधिकार और मानवता जैसे विषय किसी के विमर्श में नहीं हैं। उनकी चर्चा के केंद्र में भी नहीं, जो अपने लेखन में जन पक्षधरता का दावा करते हैं। क्या बस्तर में रोज ही मारे जा रहे जनजातीय लोगों के लिए स्वर मुखर करना जन का पक्ष नहीं है?



झीरमघाटी नक्सली हमला 2013

दम लेगी तो फिर उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। वर्ष 2000 में नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने कई क्षेत्रों में

अभूतपूर्व तरक्की की। लेकिन प्रदेश की आँख में किरकिरी समान नक्सलवाद ने राज्य के कई क्षेत्रों को अपनी गिरफ्त में

रखा और वहाँ का विकास शून्य रहा। विगत विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व



## छत्तीसगढ़ में खात्मे की ओर बढ़ा नक्सलवाद?

राज्य पुलिस ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। इनमें से ज्यादातर एनकाउंटर राज्य पुलिस के द्वारा ही किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद से नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी देखने को मिली है। केंद्र ने भी नक्सलियों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई हुई है। अब ताजा उदाहरण की बात की जाए तो जब कोर इलाके में घुसपैठ की बात आती है तो सिर्फ पांच महीनों के अंदर पुलिस ने कोर इलाकों में 32 कैंप लगाए हैं। हर साल करीब 16-17 कैंप ही लगाए जाते हैं। बेहतर को-ऑर्डिनेशन के साथ कई फोर्स ने जिले में अभियान चलाने में काफी मदद की है। ज्यादातर ऑपरेशन राज्य की फोर्स और सीआरपीएफ, कोबरा, आईटीबीपी और बीएसएफ जैसी टीमों ने चलाए हैं। उम्मीद है कि तीन साल में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। एक अच्छी सरेंडर नीति लागू करने और नक्सलवाद से ग्रसित लोगों के लिए राहत उपाय करने की प्लानिंग है। 2024 के छह महीने से भी कम समय में नक्सल विरोधी अभियानों के बाद 136 नक्सलियों को को ढेर कर दिया है। 2016 में 134 नक्सलियों को ढेर किया गया था। यह संख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस साल में अब तक 392 नक्सलियों को पकड़ा जा चुका है और 399 ने सरेंडर किया है। नक्सलियों को ढेर करने के पीछे का बड़ा राज यह है कि राज्य की पुलिस और केंद्रीय बल आपस में बेहतर तालमेल बैठ पा रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में नक्सली इलाकों में कैंप भी खोले गए हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार के राज में पांच साल में कुल 210 नक्सली को ढेर किए गए हैं।



में सबसे पहले नकेल कसी गई नक्सलवादियों पर। बस्तर जो कि प्रदेश में

नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिला है वहाँ पर 'नियद नेल्लार योजना' लागू की गई

जिससे वहाँ के रहवासियों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हो और सरकार की सारी



## नियद नेल्लानार योजना

छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार नियद नेल्लानार (आपका अच्छ गांव) नामक योजना चलाई है। वह गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, पानी की सुविधा प्रारम्भ कर समानता और विकास का एक वातावरण तैयार कर रही है। यह बात भटके हुए युवा समझ रहे हैं। इसलिए उन्हीं से पूछ रहे हैं कि उनके पुनर्वास की नीति क्या होनी चाहिए, ताकि वे मुख्यधारा से जुड़कर प्रदेश और देश की विकास में भागीदारी कर सकें। समाज नक्सलवाद की इस समस्या के हल के लिए समर्थ हैं। सरकार खुद मानती है कि अभियान मुख्य विषय नहीं है और यह तो सरकार के प्रयास का बहुत छोटा सा हिस्सा है। सरकार का मुख्य प्रयास प्रभावित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के कार्य करना है। साथ ही साथ जो युवा नक्सली विचारधारा छोड़कर आए हैं, सरकार उनके लिए कार्य कर रही है। वह उनके सर्वांगीण विकास की योजना आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति बहुत ही अच्छी है। इसे बेहतर बनाने के लिए वह किसी भी राज्य में जाकर अध्ययन करने को तैयार हैं।

जनहित की योजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों को मिल सके। इस योजना को लागू करने के पीछे राज्य सरकार की मंशा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास करना है। इस योजना ने अपने सफल परिणाम भी दिए। पहली बार यहाँ के नक्सली हिंसा से पीड़ित लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी

**केन्द्र और राज्य सरकार  
के साझा प्रयासों से खात्मे  
की ओर नक्सलवाद**

आपबीती राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अन्य लोगों से साझा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवादियों के आत्म समर्पण से जुड़ी नई योजना लागू भी लागू की है जिसके अंतर्गत प्रदेश में इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन हालिया घटना से यह साबित करती

## क्या है नक्सली समस्या का समाधान?

यूँ तो सामाजिक जीवन में हर इंसान सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन अंदाजा लगाइये कि उस व्यक्तिकी जिंदगी में कितनी पीड़ा होगी जिसकी हर सुबह-शाम डर में ही गुज़रती है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्तिको बिना वजह अपनों को खोना पड़े तो, यह न केवल चिंता का विषय है बल्कि, यह बैठकर मंथन करने वाली बात है कि हम कैसे समाज, कैसे परिवेश और कैसे वातावरण में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पिछले तीन सालों की बात करें तो इस दौरान हुए नक्सली हमलों में हजारों लोगों की मौतें हुईं। वहीं अगर सरकार की मानें तो, नक्सली हमलों में धीरे-धीरे कमी आ रही है और नक्सल प्रभावित इलाके लगातार सिमटते जा रहे हैं।

### चर्चा के प्रमुख बिंदु-

- 1967 में शुरू हुई इस समस्या को हमारी सरकारें जड़ से मिटाने में अब तक पूरी तरह सफल क्यों नहीं रहीं हैं?
- क्या तकनीकों से लैस हमारे सुरक्षा बल इस समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं? या फिर हमारी सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है?
- गौर करें तो, नक्सलवाद परिस्थिति के कारण पैदा हुई एक समस्या है और इसकी पृष्ठभूमि सामाजिक सरोकार से जुड़ी है। लेकिन, बदलते समय के साथ इसके स्वरूप में भी बदलाव आया है और अपने नए अवतार में नक्सलवाद एक राजनीतिक समस्या बन गया है। ऐसे में सवाल है कि-
- क्या नक्सलवाद की वजहों पर काम करने के बजाय सियासी दलों ने इसे शह दिया है?
- सवाल यह भी है कि सरकार ने इससे निपटने के लिये क्या-क्या पहलें की हैं?
- अगर सरकार की पहलें सही दिशा में नहीं हैं तो, इस समस्या का सही हल क्या है?
- इस लेख के जरिये हम इन्हीं पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।

हे कि प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करने की राह इतनी आसान भी नहीं है। छत्तीसगढ़

में दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर स्थित थुलथुली गांव के पास हुई मुठभेड़

में 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर प्राप्त हुई है। पिछले नौ महीने के भीतर



# नक्सलवाद : एक नजर में

नक्सलवादी विचारधारा एक आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1960 के दशक में कम्युनिस्टों यानी साम्यवादी विचारों के समर्थकों ने इस आंदोलन का आरंभ किया था। दरअसल, इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के गाँव नक्सलबाड़ी से हुई थी, इसलिये यह नक्सलवादी आंदोलन के रूप में चर्चित हो गया। इसमें शामिल लोगों को नक्सली कहा जाता है। आपको बता दें कि इस आंदोलन में शामिल लोगों को कभी-कभी माओवादी भी कहते हैं। नक्सलवादी



और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिंसा पर आधारित हैं। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा है जबकि चीनी नेता माओत्से तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित मुहिम को माओवाद का नाम दिया गया। गौरतलब है कि दोनों ही आंदोलन के समर्थक भुखमरी, गरीबी और बेरोज़गारी से आजादी की मांग करते रहे हैं। किसानों पर जमींदारों द्वारा अत्याचार और उनके अधिकारों को छीनना एक पुरानी प्रथा रही है और देश भर में इसके हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। लिहाजा, नक्सलबाड़ी के तत्कालीन किसान भी इसी समस्या का सामना कर रहे थे। आजादी के बाद भूमि सुधार की पहलें जरूर हुई थीं। लेकिन, ये पूरी तरह कामयाब नहीं रहीं। नक्सलबाड़ी किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ता चला गया और इसी के मद्देनजर किसान और जमींदारों के बीच ज़मीन विवाद पैदा हो गया। लिहाजा 1967 में कम्युनिस्टों ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की और यह अभी तक जारी है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारुमजूमदार ने कानू सान्याल और जंगल संथाल के साथ मिलकर सत्ता के खिलाफ एक किसान विद्रोह कर दिया था। 60 के दशक के आखिर और 70 के दशक के शुरुआती दौर में, नक्सलबाड़ी विद्रोह ने शहरी युवाओं और ग्रामीण लोगों दोनों के दिलों में आग लगा दी थी। देखते ही देखते, इस तरह का आंदोलन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आम हो गया और धीरे-धीरे यह ओडिशा, आंध्र

सरकार ने प्रदेश के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में पांच-पांच किलोमीटर की दूरी पर 33 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए और

योजनाबद्ध तरीके से 189 नक्सलियों को खत्म किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का तंत्र लगातार ध्वस्त हो रहा है। इसका श्रेय

दिया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। इनके परस्पर नक्सलवाद के खिलाफ

प्रदेश और महाराष्ट्र तक में फैल गया। आजाद भारत में पहली बार किसी आंदोलन ने गरीब और भूमिहीन किसानों की मांगों को मजबूती दी जिसने तत्कालीन भारतीय राजनीति की तस्वीर बदलकर रख दी। दरअसल यह आंदोलन हिंसा पर आधारित है और इसमें धनवानों और सत्ता की मदद करने वालों की हत्या कर देना एक आम बात है। सच कहा जाए तो अन्याय और गैर बराबरी से पैदा हुआ यह आंदोलन देश और समाज के लिये नासूर बन गया है।



लेकिन चिंता का विषय है कि हमारी सरकारें अभी तक इसकी काट नहीं ढूंढ सकी हैं।

### नक्सली हिंसा में कितनी कमी आई है ?

नक्सली समस्या को लेकर ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले के कमी आई है। गौरतलब है कि 2008 में 223 जिले नक्सल प्रभावित थे लेकिन, तत्कालीन सरकार के प्रयासों से इनमें कमी आई और 2014 में यह संख्या 161 रह गई। 2017 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या और घटकर 126 रह गई। गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 44 जिलों को नक्सल मुक्तघोषित कर दिया गया है जबकि 08 नए जिलों में नक्सली गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। लिहाजा, नक्सल प्रभावित कुल जिलों की संख्या अब 90 हो गई है। ये सभी जिले देश के 11 राज्यों में फैले हैं जिनमें तीस सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बताए गए हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार को सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है। आँकड़ों पर गौर करें तो पिछले एक दशक में नक्सली हिंसा में कमी आई है और कई जिलों को नक्सल गतिविधियों से मुक्त भी कराया गया है। लेकिन, गौर करने वाली बात है कि कई नए जिले ऐसे भी हैं जिनमें नक्सली गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। इसी साल गृह मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक 08 जिले ऐसे हैं जहाँ पहली दफा नक्सली गतिविधियाँ देखी गई हैं। केरल में ऐसे तीन, ओडिशा में दो और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में एक-एक जिले पाए गए हैं। ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि जब एक तरफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सिमटने के दावे हो रहे हैं तो, दूसरी तरफ नए जिलों को यह रोग क्यों लग रहा है? लिहाजा, इस पहलू पर भी ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है।

आक्रामक रूख का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा

रहे स्पेशल ऑपरेशन 'हॉट परस्यूट' और 'ड्राइव फॉर हंट' ऑपरेशन ने नक्सलियों का जीना मुहाल कर दिया है। नतीजतन, प्रदेश

में लगातार नक्सली ढेर हो रहे हैं। हर महीने जवान बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं। वहीं इसी तारतम्य में गृह मंत्री अमित शाह ने भी



कहा है की मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यकीनन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद का सफाया होगा इसके इशारे प्राप्त होने लगे हैं।

इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने लगभग 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं 801 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 742 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर कहा कि आज भी जो युवा नक्सलवाद में लिप्त हैं उनसे आग्रह है कि हथियार छोड़ कर मुख्य धारा से जुड़े। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वास के लिए बेहतर योजनाएं बनाई हैं उसका फायदा लीजिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ाई गई है। हम निरंतर गाँवों तक

बुनियादी सुविधाएँ पहुंचा रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे एरिया में हमने 32 नये कैम्प स्थापित किये हैं, जिसे वो अपनी राजधानी तक कहते थे। उनकी बटालियन के कमांडर हिडमा के गाँव में भी हमने कैम्प स्थापित किया और उसकी माँ को

भी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य नक्सलियों के बचे हुए गढ़ों को समाप्त करना और इन इलाकों में स्थाई शांति और विकास सुनिश्चित करना है। निकट भविष्य में दक्षिण बस्तर में 29 नए सुरक्षा कैम्पों की स्थापना की जाएगी, ताकि

**इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों ने लगभग 194 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं 801 नक्सली गिरफ्तार हुए एवं 742 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर कहा कि आज भी जो युवा नक्सलवाद में लिप्त हैं उनसे आग्रह है कि हथियार छोड़ कर मुख्य धारा से जुड़े। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वास के लिए बेहतर योजनाएं बनाई हैं उसका फायदा लीजिए।**

नक्सलियों के प्रभाव को खत्म किया जा सके। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में हुए सफल ऑपरेशन की तारीफ करते हुए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे भी छत्तीसगढ़ की खुफिया तकनीकी और आपसी समन्वय के आधार पर अपने अपने राज्यों में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए पूरा समर्थन देगी।

### दशकों की समस्या है नक्सलवाद

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद दशकों से एक बड़ी समस्या रही है। नक्सली राज्य के विकास में बाधक बनते रहे हैं। कई बड़े नक्सलियों ने हाल के दिनों में आत्मसमर्पण किया है, वहीं कई मारे गए या गिरफ्तार हुए। हालांकि अभी भी नक्सली रह-रह कर सिर उठाते रहते हैं। इसलिए नक्सली समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने तक इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। राज्य के विकास के लिए उद्योगीकरण को बढ़ावा

देना जरूरी है। उद्योगपतियों को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि उन्हें यहां भयमुक्त वातावरण मिलेगा। जानकारों की मानें तो पूर्ववती कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के समय में नक्सलवाद बेहद तेजी से बढ़ा और राज्य में नक्सलियों ने आतंक मचा दिया था।

**छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद दशकों से एक बड़ी समस्या रही है। नक्सली राज्य के विकास में बाधक बनते रहे हैं। कई बड़े नक्सलियों ने हाल के दिनों में आत्मसमर्पण किया है, वहीं कई मारे गए या गिरफ्तार हुए। हालांकि अभी भी नक्सली रह-रह कर सिर उठाते रहते हैं। इसलिए नक्सली समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने तक इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।**

### बस्तर में नक्सलवाद : कल और आज

यह मिथक है कि बस्तर में नक्सलवाद किसी आंदोलन, शोषण या अपने आप से पैदा हुए गुस्से की वजह से पनपा। बस्तर में आदिम समाज के पास अपना विरोध-तंत्र तथा उनकी प्रतिक्रिया देने की शैली सामाजिक संगठन में ही अंतर्निहित थी। यही कारण है यहां विद्रोहों का मौलिक व लंबा इतिहास रहा है। वस्तु स्थिति यह थी कि गोदावरी नदी के एक ओर कोण्डापल्ली सफल नहीं हो रहे थे। उन्हें नदी के दूसरी ओर बस्तर के जंगलों में अपने लड़ाकों के लिए सुरक्षित जगह बनाने का ख्याल कौंधा। उन्होंने योजना के अनुसार, 1980 के दौरान पांच से सात सदस्यों वाले अलग-अलग सात दल भेजे थे। चार दल दक्षिणी तेलंगाना के आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर और वारंगल की ओर, एक दल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तथा दो दल बस्तर की ओर भेजे गए। पहले सर्वे का काम पूरा हुआ, फिर नाच-गाना के माध्यम से जनसमूह को आकर्षित किया गया। वनवासियों को सहानुभूति हासिल करने के लिए बांस से



लेकर तेंदू पत्ता जैसे जंगल के उत्पादों की उचित मजदूरी देने की मांग उठाई गई। ठेकेदारों को गांव वालों के सामने मारा-पीटा गया। विश्व बैंक की एक योजना थी, जिसके तहत चीड़ के पेड़ लगाए जाने थे। इसका विरोध हुआ। अलग बात है कि चीड़ के पेड़ों के लिए बस्तर की जलवायु वैसे ही अनुपयुक्त है। सबसे बड़ी बात कि तेंदू पत्ता को लेकर सरकार को ठोस नीति बनानी पड़ी। ये मोटे-मोटे काम हैं, जो बस्तर में

## साथ सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए नक्सली सफल हो रहे साथ सरकार के प्रयास

घोषित हुई, सलवा जुद्धम आरंभ हुआ और सैंकड़ों राहत शिविरों में लाखों विस्थापित रहने लगे और गांवों में सन्नाटों ने बस्तियां बसाईं। जब सलवा जुद्धम का जवाब देने के लिए माओवादियों ने कोया भूमकाल मिलिशिया का गठन किया और अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों के हजारों जनजातीय बंधुओं को गृह युद्ध की आहुति बनाया। छत्तीसगढ़ की परिधि के बाहर बस्तर की नक्सली गतिविधियों पर अत्यधिक रूप



नक्सली अभियान की शुरुआत में किए गए। समानान्तर रूप से नक्सली बस्तर अंचल में अपने लिए आधार क्षेत्र भी तैयार करते रहे और खुद को शक्तिशाली बनाने में लगे रहे। कोण्डापल्ली सीतारमैया से मतभेद के बाद 1992 में मुलप्पा लक्ष्मण राव उर्फ गणपति पीपुल्स वार ग्रुप का कमांडर इन चीफ बना। 2 मार्च, 1993 को कोण्डापल्ली सीतारमैया को आंध्र पुलिस ने कृष्णा जिले में गिरफ्तार कर लिया। वर्ष

2004 से 2006 की बात है, जब कई माओवादी धड़े संगठित हुए। इसी दौरान आंध्रप्रदेश में भीषण दमनात्मक कार्रवाइयों के फलस्वरूप नक्सलियों ने अपने कांडर के 1,800 से सदस्यों को खो दिया था। बस्तर के घुसने तथा स्वयं को संरक्षित करने की दृष्टि से नक्सलियों के लिए यह उचित समय था। इसी समय अबुझमाड़ नक्सली गतिविधियों का केंद्रीय स्थल बना। इसी समय बस्तर में कई विकास परियोजनाएं

मानियत भरे आलेख प्रकाशित होते रहे। अधिकांश किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित थे। सलवा जुद्धम का राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अत्यधिक संगठित विरोध अनेकों गैर-सरकारी संगठनों तथा वाद-विशेष के बुद्धिजीवियों ने किया। मामला अदालत में भी पहुंचा। दबावों ने अंततः इस अभियान की कमर तोड़ दी। सलवा जुद्धम अध्याय का पटाक्षेप 2006 के अंत तक हो गया था।

# महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा मध्यप्रदेश

लगातार बढ़ रहा महिला अपराधों का ग्राफ



शांति के टापू माना जाने वाला मध्यप्रदेश अब महिलाओं और बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और असुरक्षित हो गया है। प्रदेश में दुष्कर्म के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों में प्रदेश बढ़ता जा रहा है। घरेलू हिंसा के साथ-साथ दुष्कर्म जैसी वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। बीते साल प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध के 32,765 अपराध घटित हुए। बीते कुछ महीनों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे महानगर में छोटी बच्चियों के साथ रेप की कई वारदातें हुईं। जाहिर है ऐसे में विपक्ष बिगड़ती कानून व्यवस्था के ज़रिए सरकार पर हमला बोलेगा ही। सवाल तो यह भी है कि यदि अपराध हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

#### विजया पाठक

शांति के टापू माना जाने वाला मध्यप्रदेश अब महिलाओं और बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और असुरक्षित हो गया है। प्रदेश में दुष्कर्म के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों में प्रदेश बढ़ता जा रहा है। घरेलू हिंसा के साथ-साथ दुष्कर्म जैसी वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं।

**मोहन यादव  
सरकार की  
कानून व्यवस्था  
कठघरे में**

बीते साल प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध के 32,765 अपराध घटित हुए। बीते कुछ महीनों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे महानगर में छोटी बच्चियों के साथ रेप की कई वारदातें हुईं। जाहिर है ऐसे में विपक्ष बिगड़ती कानून व्यवस्था के ज़रिए सरकार पर हमला बोलेगा ही। सवाल तो यह भी है कि यदि अपराध हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक अपराधी कानून की कमजोरियों का फायदा



उठाकर ऐसी जघन्य वारदातों को अंजाम देते रहेंगे? क्या सरकार इसके लिए निर्णायक कदम उठाएगी? यह भी देखने में आया है कि अधिकतर मामले में आरोपित करीबी होते हैं। अपराधों में सबसे ज्यादा शिकायतें पति और रिश्तेदारों को लेकर ही आती है। प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ने को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर निशाना साध रही है। मध्यप्रदेश में महिलाओं, बच्चियों पर लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं जिसे लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। हाल ही में राजधानी

**मध्यप्रदेश में महिलाओं, बच्चियों पर लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं जिसे लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है। हाल ही में राजधानी भोपाल में प्रदेश के सभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक अलग तरीके सरकार को घेरने की कोशिश की थी।**

भोपाल में प्रदेश के सभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक अलग तरीके सरकार को घेरने की कोशिश की थी। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे में कांग्रेसियों ने सामूहिक उपवास शुरू किया था। इस उपवास में कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुंच कर एकता का संदेश दिया था। जिसमें कांग्रेस के दिग्गज शामिल हुए। इसके अलावा बेटियों की सुरक्षा के लिए 05 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया था। जबकि 07 अक्टूबर को कैंडल मार्च, 08 अक्टूबर को ब्लॉक स्तरीय उपवास एवं कन्या पूजन किया गया। 14 अक्टूबर को बेटी बचाओ ज्ञापन दिया गया था।



इनका कहना है-

## महिलाओं पर अत्याचार का गढ़ बन गया मध्यप्रदेश

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश दिन-प्रतिदिन महिलाओं और बच्चियों के लिए असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। पिछले दो महीने में जिस तरह से बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार एवं सामूहिक दुष्कर्म के समाचार मीडिया में आ रहे हैं, उससे महिला सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। समाचार इतने भयानक हैं कि महू में सेना की सुरक्षा वाले इलाके में सेना अफसरों के साथ मौजूद युवतियों से बलात्कार की घटना सामने आती है। भोपाल में स्कूल में छोटी बच्ची दरिंदगी का शिकार होती हैं। छतरपुर में बलात्कारियों के हौसले इतने बढ़ जाते हैं कि वह पीड़िता के घर में घुसकर परिजनों को गोली मार देता है और खंडवा में घर के बाहर खड़ी बलात्कार पीड़िता के उपर आरोपी का बेटा पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। 24 सितंबर को प्रदेश के चार शहरों जबलपुर, रीवा, मैहर और दतिया से सामूहिक बलात्कारों की खबर सामने आती है। इन सब घटनाओं के बीच मध्यप्रदेश की सरकार कुंभकरण की नींद सो रही है और महिला सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस उपाय अब तक नहीं कर रही है।



कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री

आज हालत यह है कि महिला आयोग में न अध्यक्ष है और न ही सदस्य, महिलाओं से जुड़े हुए 24 हजार मामले भी पेंडिंग हैं। यह भाजपा सरकार की अकर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण और परिणाम है। आगर मालवा की दुष्कर्म पीड़िता हो, चाहे इंदौर की साइबर ब्लैकमेल पीड़िता, किसी को पुलिस न्याय नहीं दिला पा रही है, तभी तो उन्होंने महिला आयोग का रुख किया, लेकिन, अब वहां भी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या यही

### क्यों नहीं थम रहे दुष्कर्म के मामले?

- 2022 में POC SO संबंधित धाराओं के तहत कुल 5951 मामले दर्ज।
- रेप के 3,653 मामले
- यौन उत्पीड़न के 2,233 मामले दर्ज।



## बलात्कार के मामले में मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर

कमलनाथ ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। इस अवधि में मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3029 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 3049 महिलाएं छेड़खानी का शिकार हुईं और 1445 महिलाएं शारीरिक शोषण का शिकार हुईं। प्रदेश में पोस्को से जुड़े अपराधों में 5951 मामले दर्ज किए गए इनमें से बलात्कार के 3641 मामले हैं। महिलाओं और नाबालिग से हुए बलात्कारों को देखें तो प्रदेश में हर दिन 18 बलात्कार हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 3,500 महिलाएं प्रतिवर्ष महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचती हैं अर्थात् 9 से 10 महिलाएं प्रतिदिन, इन महिलाओं को न्याय नहीं मिलने की जिम्मेदार सरकार है। राज्य में 2023-24 में महिला प्रताड़ना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मध्यप्रदेश में जहां एक ओर मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण और बेटियों को सम्मान देने की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर प्रदेश के माथे पर एक बड़ा कलंक महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और अत्याचार का लगा हुआ है। खुद केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि देश के दिल मध्यप्रदेश में हर दिन औसतन 17 से 18 दुष्कर्म के मामले देखने को मिलते हैं।

आपकी महिला न्याय नीति है? आयोग के नियमानुसार किसी भी शिकायत पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होती है, परंतु आपकी सरकार नियम और कानून से परे

है। सरकार की व्यक्तिगत रूचि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर एफआईआर कर पॉक्सो एक्ट लगाने में है।

एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि

राज्य में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 32765 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में 30673 मामले दर्ज हुए थे, यानी साल भर में 2092 अपराध बढ़े।

बलात्कार के मामले मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। 2022 में मध्य प्रदेश में 3,046 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। नाबालिगों से बलात्कार के मामले में भी मध्यप्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। राज्य में 2022 में छत्रच्छ संबंधित धाराओं के तहत कुल 5951 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 3,653 मामले बलात्कार के हैं। 2,233 मामले यौन उत्पीड़न के और 42 मामले उत्पीड़न से संबंधित थे। देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। देश में मध्य प्रदेश इस मामले में तीसरे स्थान पर था। बच्चों से छेड़खानी के मामले भी प्रदेश में ज्यादा हैं। प्रदेश के थानों में 5996 केस दर्ज हैं। पिछले दो सालों में इन मामलों में कमी जरूर आई है, पर अभी मध्य प्रदेश में महिला अपराध लगातार हो रहे हैं। फिन्हाल गृह विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास है। वैसे पुलिस के आंकड़ों की मानें तो प्रदेश में बलात्कार सह हत्या के प्रकरणों में 14.3 प्रतिशत की कमी, दुष्कर्म के प्रयास में

## सबसे ज्यादा महिलाएं मध्यप्रदेश से गुम हुईं

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 के बीच देशभर में 13 लाख 13 हजार लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं, इनमें से सबसे अधिक मामले मध्यप्रदेश के हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (ःकडए) द्वारा जुटाए गए आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2021 के बीच पूरे देश में 18 साल से अधिक आयु की 10 लाख 61 हजार 648 महिलाएं लापता हुईं। वहीं इस दौरान 18 साल से कम आयु की दो लाख 51 हजार 430 लड़कियां गायब हुई हैं। इनमें से एक लाख 60 हजार 180 महिलाएं और 38 हजार 234 लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब हुई हैं।



## नाबालिगों बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में नंबर वन स्टेट

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में देश भर में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 33 हजार 36 आए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा 3 हजार 515 मामले मध्यप्रदेश में दर्ज किए गए थे। वहीं कुल ज्यादाती के मामलों में 6 हजार 462 एमपी के ही थे। आंकड़ों को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में हर दिन लगभग 17 से 18 रेप औसतन हो रहे हैं।

35.7 प्रतिशत कमी और दहेज हत्या के प्रकरण 10.7 प्रतिशत घटे हैं। लगातार हो रहे अपराधों से इन आंकड़ों पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। हमारे प्रदेश में बलात्कार की खबरें आम सी हो गई हैं। बच्चियों की सुरक्षा के जितने भी दावे किए गए हैं, सबकी हवा निकलती दिख रही है। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

**महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा के संबंध में पुलिस कठघरे में**

प्रदेश सरकार भले ही महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने कर दावे करती है लेकिन ताजा घटनाओं को देखें तो महिलाओं के साथ अपराध बढ़ गए हैं। बीते कुछ दिनों में महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा के संबंध में प्रदेश की पुलिस कठघरे में खड़ी नजर आ रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि





## बाल शोषण के मामले में भी मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर

एनसीआरबी के 2022 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश बाल शोषण के मामले में भी शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 20762 मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरे स्थान में शामिल मध्य प्रदेश में 20415 अपराध दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 18682, राजस्थान में 9370 और पश्चिम बंगाल में 8950 मामले दर्ज हुए हैं।

भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है। महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। अपराधियों की निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हों और गंभीरता से विचार करें कि देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो प्रदेश को अपराधों की राजधानी बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। यहां महिला, दलित, आदिवासी, जवान, किसान, सब पर अत्याचार हो रहा है।

आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 15 मिनट में एक दुष्कर्म होता है- नेशनल क्राइम

## क्राइम अर्गॉस्ट वूमैन में टाॅप में मध्यप्रदेश

- देश में 2019-2021 में 13,13,000 महिलाएं-लड़कियां लापता।
- 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां मध्यप्रदेश से गायब।
- 2021 में नाबालिग से दुष्कर्म के 3,515 मामले मध्यप्रदेश में।
- नाबालिगों से दुष्कर्म के ये मामले देशभर में सबसे ज्यादा।
- 2020 में 5,598 रेप के मामले मध्यप्रदेश में हुए थे दर्ज।
- इसमें 3, 259 मामले नाबालिगों से दुष्कर्म के थे।
- 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 32765 मामले दर्ज।
- 2021 में 30673 मामले दर्ज हुए।
- साल भर में 2092 अपराध बढ़े।
- 2022 में 3,046 रेप केस मध्यप्रदेश में।



रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 15 मिनट में एक दुष्कर्म होता है। ऐसे में देखा जाए तो हर घंटे 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। मध्य प्रदेश भी महिला अपराधों के मामले में पीछे नहीं है। 2022 की बात करें तो पूरे देश में दुष्कर्म के 31 हजार से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। उनमें से राजस्थान में 5399, उत्तर प्रदेश में 3690 और मध्यप्रदेश में 3039 केस दर्ज हुए थे। देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। देश में मध्य प्रदेश इस मामले में तीसरे स्थान पर था। बच्चों से छेड़खानी के मामले भी प्रदेश में ज्यादा हैं। प्रदेश के थानों में 5996 केस दर्ज हैं। पिछले दो सालों में इन मामलों में कमी जरूर आई है, पर अभी मध्य प्रदेश में महिला अपराध लगातार हो रहे हैं। पद संभालने के 15 दिनों के भीतर ही पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर गृह विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने ढिलाई करने वाले कई पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर भी किया था। सीएम की सख्ती के बाद भी आए दिन महिलाओं के साथ अपराध सामने आ ही रहे हैं। जब मप्र की शिवराज सरकार ने नया विधेयक पेश किया था तो प्रदेश के प्रविधान की तुलना उत्तर कोरिया, सउदी अरब, चीन, मिस्र, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान जैसे देशों की सजा से की जाने लगी थी। 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने भी नाबालिगों के लिए कानून बनाया था। ये कानून पाक्सो यानी प्रोटेक्शन आफचिल्ड्रन प्रम सेक्सुअल अफेंस एक्ट था। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों, दोनों पर लागू होता है। इसके साथ ही प्रदेश में दुष्कर्म के दोषियों के मकान गिराने जैसी कार्रवाई भी लगातार की जाती है। इतने सख्त कानून और सजा के प्रविधान भी अपराधों को कम करने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं।



कमलनाथ,  
पूर्व मुख्यमंत्री म.प्र.

# कर्ज के दलदल में डूब रहा है मध्यप्रदेश के नौजवानों का भविष्य

पिछले 5 वर्ष में प्रदेश सरकार ने सिर्फ कर्ज के ब्याज के रूप में एक लाख करोड़ रुपए चुकाए हैं। हाल यह हो गया है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। प्रदेश सरकार के बजट में कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए अलग से मद बनाना पड़ता है। ऐसे में सवाल यह है कि बेतहाशा कर्ज लेकर आखिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने पिछले कुछ वर्ष में प्रदेश की जनता का क्या भला किया है?

अब समय आ गया है कि जनता के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए राजकोष के धन का इस्तेमाल ईमानदारी, पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अगर इस तरह से वित्तीय अनुशासन नहीं

अपनाया गया तो प्रदेश दिवालियापन की कगार पर पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा और वन्य जीवन ने इसे पूरे देश में विशिष्ट स्थान दिया है। किसानों की मेहनत

से मध्य प्रदेश सोया प्रदेश कहलाता है तो अपने घने जंगलों में बड़ी संख्या में विचरण करने वाले बाघों के कारण इसे पूरे देश में बाघ प्रदेश का दर्जा भी मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के लोग ईमानदार और मेहनती हैं। इस



तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पास देश के सबसे आगे बढ़ते हुए समृद्ध राज्य होने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं।

लेकिन इतना सकारात्मक वातावरण होने के बावजूद पिछले कुछ वर्ष से यह देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबोती जा रही है। अगर आंकड़ों पर निगाह डालें तो अब तक मध्य प्रदेश के उपर करीब 04 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। प्रदेश सरकार ने योजनाओं पर जो खर्च घोषित किया है उसकी पूर्ति के लिए चालू वित्त वर्ष में ही मध्य प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड 88540 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ेगा। पिछले वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार ने 55708 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इस तरह एक वित्त वर्ष में ही कर्ज में 38 प्रतिशत की वृद्धि होने जा रही है। मध्य प्रदेश में पहले भाजपा की शिवराज सिंह चौहान सरकार और अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार कर्ज लेती चली जा रही है।

पिछले 5 वर्ष में प्रदेश सरकार ने सिर्फ कर्ज के ब्याज के रूप में एक लाख करोड़ रुपए चुकाए हैं। हाल यह हो गया है कि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। प्रदेश सरकार के बजट में कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए अलग से मद बनाना पड़ता है। ऐसे में सवाल यह है कि बेतहाशा कर्ज लेकर आखिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने पिछले कुछ वर्ष में प्रदेश की जनता का क्या भला किया है? प्रदेश की हालत पर नजर डालें तो पेट्रोल और डीजल के उपर सबसे ज्यादा वेट लेने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। इस तरह प्रदेश की जनता डीजल और पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत चुकाने को मजबूर होती है। अगर प्रदेश की बिजली दरें देखें तो भी आप पाएंगे कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश का नागरिक प्रति यूनिट कहीं ज्यादा बिजली का बिल चुका रहा है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन और



मकान की रजिस्ट्री में भी मध्य प्रदेश सरकार देश के संपन्न राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा टैक्स नागरिकों से वसूल कर रही है।

**उदारवादी अर्थव्यवस्था में यह सामान्य धारणा है कि अगर कोई सरकार कर्ज लेती है तो वह जनकल्याण और विकास के कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जन कल्याण के कार्यों पर अतिरिक्त खर्च करना तो दूर अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन तक को पूरा नहीं कर रही है।**

इस तरह से देखा जाए तो एक तरफ तो मध्य प्रदेश के नागरिक कर्ज के बोझ से दब रहे हैं तो दूसरी तरफ वह देश में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले नागरिक हैं। सवाल यह उठता है कि नागरिकों से भरपूर टैक्स वसूल करने के बावजूद प्रदेश सरकार आखिर क्यों अपने संसाधनों से प्रदेश का खर्च नहीं चल पाती और लगातार कर्ज लेती जा रही है?

उदारवादी अर्थव्यवस्था में यह सामान्य धारणा है कि अगर कोई सरकार कर्ज लेती है तो वह जनकल्याण और विकास के कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जन कल्याण के कार्यों पर अतिरिक्त खर्च करना तो दूर अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन तक को पूरा नहीं कर रही है। पाठकों को याद होगा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2700





रूपये प्रति क्विंटल और धान का समर्थन मूल्य 3100 रु पर प्रति क्विंटल करने का वादा किया था। लाइली बहना योजना की राशि बढ़कर 3000 रूपये प्रति माह करने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा भी किया था। प्रदेश में हर महीने 2 लाख नए रोजगार सृजित करने का वादा भी भाजपा ने किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। लेकिन इनमें से एक भी वादे पर भाजपा सरकार ने अमल नहीं किया है। यही नहीं, शिवराज सरकार के दौरान मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी देने की योजना भी चुनाव से ठीक पहले अमल में लाई गई थी। लेकिन मोहन यादव सरकार में ना तो टॉपर छात्रों को लैपटॉप बांटे जा रहे हैं

और ना ही किसी को स्कूटी मिली। ऐसा नहीं है कि यह सब करना असंभव है। साल 2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर दोगुनी की

**2019 में मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर दोगुनी की गई थी। संबल योजना की जगह नया सेवरा योजना लाकर श्रमिक वर्ग को आर्थिक लाभ पहुंचाए गए थे। 100 में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा पहले चरण में 27 लाख किसानों का कर्ज भी कांग्रेस सरकार ने माफ किया था।**

गई थी। संबल योजना की जगह नया सेवरा योजना लाकर श्रमिक वर्ग को आर्थिक लाभ पहुंचाए गए थे। 100 में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा पहले चरण में 27 लाख किसानों का कर्ज भी कांग्रेस सरकार ने माफ किया था। 1000 गौशालाओं का निर्माण कराया गया था और महाकाल कॉरिडोर के निर्माण के लिए 355 करोड रूपए आवंटित किए थे। इस तरह के कल्याणकारी कार्यों पर बड़ी मात्रा में बजट आवंटित करने के बावजूद मेरी सरकार के दौरान कर्ज लेने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया गया था। यह सब उदाहरण इसलिए पाठकों के सामने रखे जा रहे हैं ताकि यह तस्वीर साफ हो कि अगर सरकार वाकई कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य करना चाहती है तो प्रदेश को अनावश्यक कर्ज के दलदल में डाले बिना भी जनकल्याण के काम किये जा सकते हैं।

मैंने अपने कार्यकाल में सरकारी आयोजन, प्रदर्शनों, विज्ञापनों और इवेंटबाजी पर फिजूल खर्ची को अत्यंत सीमित कर दिया था। इससे सरकारी खजाने पर बोझ में कमी आई थी। लेकिन इस तरह की कोई सोच वर्तमान सरकार में नजर नहीं आती। बल्कि इस बात का शक होता है कि भाजपा सरकारें जानबूझकर इस तरह की परियोजनाओं को मंजूरी दे रही हैं, जिनमें जनकल्याण कम और भ्रष्टाचार के माध्यम से सत्ताधारी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं

मूर्तियों का गिरना और अभी पिछले दिनों महाकाल मंदिर के पास एक दीवार ढह जाने से दो लोगों की मृत्यु हो जाना निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का उदाहरण हैं। बारिश के मौसम में प्रदेश की सड़कें जिस तरह से उखड़ गई हैं, वह बताता है कि निर्माण कार्यों में किस तरह का घोटाला हुआ है। नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, आरक्षक भर्ती घोटाला, सतपुड़ा भवन में बार-बार आग लगना, भाजपा के भ्रष्टाचार के जीते जागते सबूत हैं।

अगर फिजूल खर्ची को समझना है तो भोपाल के बीआरटी कॉरिडोर को देखा जा सकता है कि पहले तो सैकड़ों करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया। इसके कारण कई वर्ष तक जनता को परेशानी भुगतनी पड़ी और बाद में कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके इसे तोड़ा गया। अगर विस्तृत अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा की कम से कम 1000 करोड़ रुपए सरकारी रैलियों में खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के आयोजनों में भी बैंकडोर



का कल्याण अधिक हो। आप सब जानते हैं कि किस तरह शिवराज सरकार और अब मोहन सरकार में पैसा दो, काम लो का मंत्र जपा जा रहा है। इस तरह के मामलों की अगर निष्पक्ष जांच हो तो भ्रष्टाचार और इसके संरक्षकों के नाम जनता के सामने स्पष्ट रूप से आ जाएंगे। लेकिन जांच के बिना भी निर्माण कार्यों में होने वाला भ्रष्टाचार तो समय-समय पर जनता के सामने आता ही रहता है। महाकाल लोक में

**आप सब जानते हैं कि किस तरह शिवराज सरकार और अब मोहन सरकार में पैसा दो, काम लो का मंत्र जपा जा रहा है। इस तरह के मामलों की अगर निष्पक्ष जांच हो तो भ्रष्टाचार और इसके संरक्षकों के नाम जनता के सामने स्पष्ट रूप से आ जाएंगे।**

से सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है। भाजपा के सदस्यता अभियान में जिस तरह सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, वह अपने आप भ्रष्टाचार को दिखा रहा है। भाजपा सरकारों की इन नीतियों का परिणाम है कि कर्ज का बोझ तो बढ़ा ही है, हर वर्ष बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को औने-पौने दाम पर बेचा जा रहा है। सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम खस्ताहाल होते जा रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी



से जुड़े लोग अपने महल करते खड़े करते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि जनता के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए राजकोष के धन का इस्तेमाल ईमानदारी, पारदर्शिता और प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। अगर इस तरह से वित्तीय अनुशासन नहीं अपनाया गया तो प्रदेश दिवालियापन की कगार पर पहुंच जाएगा। यह सब परिस्थितियों बहुत कल्पनिक नहीं हैं। हम देख चुके हैं कि कुछ वर्ष पूर्व इसी तरह के बेतहाशा कर्ज के कारण ग्रीस दिवालिया हो गया था। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका कर्ज के दलदल में फंसकर अपने सामरिक महत्व के ठिकाने एक अन्य देश को सौंपने को मजबूर हुआ है और कुछ वर्ष पूर्व वहां का कर्ज का संकट राजनीतिक और सामाजिक संकट में बदल गया था। हाल के दिनों में पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और जन विद्रोह के बीज भी वित्तीय अनुशासन की कमी में छुपे हुए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरे के साथ हुए हादसों से सबक ले। वित्तीय अनुशासन के साथ ही दूसरा काम मध्य प्रदेश की सरकार को यह करना चाहिए कि प्रदेश के संसाधनों को और अधिक विकसित करे। प्रदेश के मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग हो सके तथा सार्वजनिक

और निजी क्षेत्र का निवेश मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाए। यह निवेश उस तरह की बिजनेस समिट से नहीं आ सकता जैसी कि पहले शिवराज जी और अब मोहन यादव जी कर रहे हैं। इन सम्मेलनों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश लाने से ज्यादा अखबारों में प्रायोजित खबरें छपवाने का है। शिवराज जी के पूरे कार्यकाल में जितने निवेश का दावा किया गया था, उतना निवेश तो पिछले 10 वर्ष में पूरे देश में नहीं आ सका है। इसलिए हैडलाइन मैनेजमेंट करना एक बात है और प्रदेश में सच्चा निवेश लाना दूसरी बात है। निवेश के लिए सबसे बड़ी चीज है- भरोसा। लेकिन जब प्रदेश की कानून व्यवस्था ही सुरक्षित ना हो, प्रदेश में दलित आदिवासी और महिलाओं पर अत्याचार की खबरों से अखबार रंगे हुए हों तो प्रदेश के बाहर का उद्योगपति प्रदेश को लेकर क्या छवि अपने मन में बनाएगा? मोहन सरकार की बुलडोजर नीति ने जनता के मन में और निवेशकों के मन में भी यह बात बैठा दी है कि प्रदेश में कानून का शासन नहीं है।

मुख्यमंत्री जी जो स्वयं गृहमंत्री भी हैं उन्हें इन बातों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि 'सरकार वही है जो शांति स्थापित करे'

लेकिन यहां तो ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं में ही प्रदेश में अशांति पैदा करने की होड़ लगी हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को सबसे पहले वित्तीय अनुशासन अपनाना होगा फिर अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी, उसके बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना होगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य करनी होगी, प्रदेश में सच्चा निवेश लाना होगा, तब जाकर मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल से बचाया जा सकेगा। और जब कर्ज का बोझ कम हो जाएगा तब जनता के उपर टैक्स का बोझ कम करने की शुरुआत की जा सकेगी। इस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा, अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी, समाज के वंचित वर्गों की पेंशन में वृद्धि की जा सकेगी और एक खुशहाल मध्यप्रदेश का निर्माण किया जा सकेगा। अगर इस चुनौती पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो कर्ज का यह मर्ज मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डुबा देगा। इसलिए सत्ता के निहित स्वार्थ से उपर उठकर प्रदेश के भविष्य पर ध्यान देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए।

# ट्रंप की जीत के भारत के लिए मायने

ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए कैसा रहेगा, यह तो उनके जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद ही पता चलेगा। ट्रंप को अब चीन या बहुपक्षवाद की तुलना में उनके उद्देश्यों के लिए अधिक गंभीर बाधा के रूप में फिर से स्थापित किया गया है।

## डॉ. सत्यवान सौरभ

डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए व्यावसायिक रूप से चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। ट्रंप की उल्लेखनीय वापसी के वास्तविक महत्व को समझने के लिए, हमें भावनाओं से आगे बढ़कर निहितार्थों की ओर बढ़ना होगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। निजी रिश्तों के साथ ही साथ दोनों देशों के आपसी हितों का तालमेल या टकराव नीतियों की दिशा तय करता है। इस लिहाज से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए कैसा रहेगा, यह तो उनके जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद ही पता चलेगा। ट्रंप को अब चीन या बहुपक्षवाद की तुलना में उनके उद्देश्यों के लिए अधिक गंभीर बाधा के रूप में फिर से स्थापित किया गया है। डीप स्टेट के लिए बदतर यह है कि इस बात की पूरी संभावना है कि यूक्रेन और गाजा में चल रहे दोनों युद्ध या तो संप्रभु बहुपक्षीय समन्वय द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे, या उन्हें सामान्य रूप से व्यवसाय की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कालीन के नीचे दबा दिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान डेमोक्रेट तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेट के बीच कहर बरपाया है और लिज चेनी जैसे सच्चे रिपब्लिकन



राजघराने ने डेमोक्रेट के लिए खुलकर प्रचार किया। पहली नजर में यह भ्रामक लग सकता है, यहां तक कि अजीब भी, लेकिन ऐसा तब होता है जब राजनीतिक विचारधारा उतनी ही तेजी से खरगोश के बिल में चली जाती है जितनी कि अमेरिका में। अगर

पार्टियों को अब यह नहीं पता कि वे किस लिए खड़े हैं, तो कल्पना करें कि आम राजनेता, पार्टियों के कार्यकर्ता और मतदाता कितने अमित होंगे? अमेरिका एक तरह से भारत की तरह है, जो इस सदी की शुरुआत में नई दिशा की तलाश में था, चीजों को

हिलाने और एक नया रास्ता बनाने के लिए दो आम चुनाव, एक नीरस दशक और नरेन्द्र मोदी के आगमन की जरूरत पड़ी। व्यवसायी ट्रंप के लिए खातों को संतुलित करना और व्यापार घाटे को कम करना एक स्वाभाविक कार्य है, जिसे वे 2016 से 2020 तक की तरह ही लगन से अपनाएंगे।

ट्रंप के पहले कार्यकाल की रणनीति से प्रेरणा लेते हुए हम अमेरिका से चीन, भारत और यूरोप जैसे दुनिया के सबसे बड़े उर्जा बाजारों में तेल और गैस के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। महामारी तक उन्होंने यही सफलतापूर्वक किया और विडंबना यह है कि जो बाइडेन ने भी इसे दोहराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। पहले क्रम के प्रभाव अमेरिका के लिए अच्छे हैं क्योंकि अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधि का मतलब है अधिक नौकरियां, आर्थिक विकास, कम व्यापार घाटा और कम मुद्रास्फीति। तेल, विशेष रूप से शेल तेल ने किसी भी अन्य क्षेत्र की

तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में अधिक योगदान दिया और ऐसा फिर से हो सकता है।

दूसरा पहलू यह है कि ट्रंप के भीतर की ओर देखने से भारत में कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं और हम कुछ वीजा युद्ध देख सकते हैं। चीन और भारत को अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद करने के लिए राजी करना कूटनीतिक मोर्चे पर एक ईमानदार समझौता है, जिसका सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से मतलब होगा कि भारत और चीन को घरेलू मामलों में बहुत अधिक अमेरिकी हस्तक्षेप के बिना अपनी बढ़ती वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा। निश्चित रूप से, कुछ शोर-शराबा होगा।

इसकी प्रतिक्रिया में, यह संभव है कि सउदी अरब जैसे बड़े तेल और गैस निर्यातक बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए एकतरफा कीमतों में कटौती कर सकते हैं, जबकि अमेरिका कतर को

निचोड़ने और ईरान को खेल से बाहर रखने के लिए अपने सभी शेष प्रभाव का उपयोग करता है। इस खेल की प्रगति का एक संकेतक यह है कि यह देखने के लिए प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या भारत ईरान से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू करता है या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो वैश्विक गतिशीलता कैसे बदलेगी, इस पर सभी दांव बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अमेरिका ने बहुध्रुवीयता को नई वैश्विक वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया है।

यूक्रेन और गाजा में चल रहे दो युद्धों पर अमेरिका की स्थिति में किसी तरह की वापसी होगी। दोनों युद्ध या तो बहुपक्षीय संप्रभुता के आदेश से समाप्त हो जाएंगे, या फिर सामान्य स्थिति में वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बेरहमी से दबा दिया जाएगा। अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए जल्द से जल्द यह सामान्य ड्रॉ जाना चाहिए, क्योंकि, हम भूल न जाएं, महामारी



के बाद एक रिकवरी वर्ष प्राप्त करने के बजाय, हमें दो बदनसूरत छद्म युद्ध, बढ़ती मुद्रास्फीति और दुर्बल करने वाले व्यापार व्यवधान मिले, कुछ ऐसा जिससे भारत केवल इसलिए बच गया क्योंकि हमने रूस पर पश्चिम के प्रतिबंधों को चतुराई से दरकिनार कर दिया।

अब आगे अमेरिकी चुनावी सुधारों पर अब गंभीरता से बहस शुरू होगी। व्यवस्था टूट चकी है और इसे ठीक करने की जरूरत है। सधार किस तरह की रू परेखा अपनाएगा, यह केवल विस्तार का विषय है, लेकिन, सैद्धांतिक रूप से इसकी आवश्यकता की जरूरत होगी।

डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में अमेरिका की सत्ता संभाल लेंगे। ट्रंप प्रशासन की संभावित आर्थिक नीतियों से दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकांश बड़े आर्थिक ताकत वाले देश असमंजस में हैं। ऐसे में एसबीआई की शोध इकाई की तरफ से जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियों से भारत भी अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा लेकिन दीर्घावधि में इन नीतियों का भारत पर सकारात्मक असर ही होगा।

नया निर्यात बाजार खोजना होगा। भारत को अपने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार करना होगा, नया निर्यात बाजार खोजना होगा और आत्मनिर्भर होने की तरफ से ज्यादा मजबूती से बढ़ना होगा। यही नहीं ट्रंप अगर चीन के खिलाफ कारोबारी युद्ध की शुरुआत करते हैं तो इसका फायदा भी भारत को होगा। फार्मा, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र में सप्लाइ चैन में जो बदलाव होगा, उसमें भारत लाभान्वित रहेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी भारत के खिलाफ कुछ आर्थिक कदम उठाए थे जैसे भारत को जेनेराइलज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफ़ेरेन्स (जीएसपी) से हटा दिया था

लेकिन अंतोगत्वा भारत पर इसका कोई उल्टा असर नहीं हुआ। उल्टा जिन भारतीय उत्पादों के आयात पर अमेरिका ने ज्यादा शुल्क लगाया, उनका निर्यात लगातार बढ़ा है।

**अधिक शुल्क के बावजूद बढ़ा निर्यात**  
वर्ष 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25 फीसद, अल्यूमिनियम पर 10 फीसद, वाशिंग मशीन पर 35 फीसद का उत्पाद शुल्क लगाया लेकिन वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच भारत का स्टील निर्यात 44 फीसद तक बढ़ गया। फुटवियर, मिनरल्स, रसायन, इलेक्ट्रिकल व मशीनरी निर्यात

लगातार अमेरिका में नये निवेश की बात करते हैं।

ट्रंप प्रशासन की तरफ से उठाये जाने वाले कदम से भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रभावित हो सकता है। मगर भारत अब पूर्व की तरफ सिर्फ अमेरिकी निवेश पर आश्रित नहीं है। इसी तरह से दूमरी बड़ी चुनौती भारत की आईटी कंपनियों के लिए पैदा हो सकती है क्योंकि ट्रंप एच1बी वीजा देने की प्रक्रिया को कठोर बनाने के पक्षधर रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में देखा गया था कि हर वर्ष तकरीबन 10 लाख पेशेवरों को ही वीजा



भारत से बढ़ा है जो बताता है कि भारत कई उत्पादों के मामले में चीन के मुकाबले वैश्विक सप्लाइ चैन में होने वाले बदलावों का ज्यादा फायदा उठाने की स्थिति में है।

रिपोर्ट यह भी कहती है कि ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में डॉलर के मुकाबले रूपये में भारी गिरावट की बात सही नहीं है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारतीय रुपया सिर्फ 11 फीसद कमजोर हुआ है। इससे ज्यादा की गिरावट बाइडन प्रशासन के कार्यकाल में हुई है। हां, रिपोर्ट में एक नकारात्मक असर जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर हो सकता है वह विदेशी निवेश के तौर पर आ सकता है। ट्रंप

दिया गया था जो बाइडन प्रशासन में बढ़कर 14 लाख सालाना हो गया है।

अगर ट्रंप फिर से ऐसा करते हैं कि अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करने वाली भारतीय आईटी कंपनियों को वहां स्थानीय तौर पर ही लोगों को नौकरी पर रखना पड़ सकता है जिससे उनकी वित्तीय बोज़ बढ़ेगा। लेकिन इसका सकारात्मक असर यह होगा कि इससे भारत में मैनुफैक्चरिंग करने पर ज्यादा जोर बढ़ेगा और अत्मनिर्भर भारत का नारा ज्यादा मजबूत होगा।



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



## अब मिलेगी समय पर सहायता...

सड़क, औद्योगिक दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा  
की स्थिति में निःशुल्क वायु परिवहन सेवा



## पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा संचालन प्रारंभ

“ हमारी सरकार प्रदेश की जनता को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हुए स्वस्थ मध्यप्रदेश के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। अब प्रदेश में गंभीर रोगियों को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए उचित समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा ”

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री



योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 9111777858

सशुल्क एयर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, सम्पर्क करें : 0755-4092530

- आयुष्मान कार्ड धारक को प्रदेश व देश में कहीं भी इलाज हेतु शासकीय और आयुष्मान सम्बद्ध अस्पताल में निःशुल्क सुविधा
- आयुष्मान कार्ड धारक न होने पर प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन सुविधा जबकि प्रदेश के बाहर निर्धारित शुल्क पर परिवहन सुविधा
- सड़कों या औद्योगिक स्थलों पर होने वाली दुर्घटना, हृदय रोगी या जहर से प्रभावित व्यक्ति को अब मिल सकेगा अच्छे चिकित्सा संस्थानों में समय पर इलाज
- अस्पताल द्वारा मरीज की स्थिति की गंभीरता की जांच के उपरांत मिल सकेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा

### एयर एम्बुलेंस सेवा की अनुमति

- दुर्घटना प्रकरण में संभाग के अंदर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा
- दुर्घटना अथवा अन्य आपदा की स्थिति में संभाग के बाहर परिवहन हेतु स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा
- दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य गंभीर प्रकरणों में प्रदेश के अंदर संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त द्वारा
- प्रदेश के बाहर गंभीर रोगी या दुर्घटना पीड़ित आयुष्मान कार्डधारी होने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा
- सशुल्क परिवहन हेतु एन.एच.एम. कार्यालय स्तर पर अनुमति मिलेगी

- रोगी/पीड़ित को एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए संजीवनी 108 एम्बुलेंस होगी उपलब्ध
- एयर एम्बुलेंस सेवा में हृदय रोग, श्वास और तंत्रिका संबंधी बीमारियों, नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याएं, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण तथा आपदा की स्थिति को संभालने के लिये प्रशिक्षित चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ रहेगा मौजूद
- हवाई परिवहन के दौरान रोगी/पीड़ित के लिए ₹ 50 लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान



## धार्मिक स्थलों की यात्रा अब सुखद और आसान



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



हम प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और अन्य पर्यटन केंद्रों तक हवाई सुविधा से आवागमन को और अधिक सुलभ बना रहे हैं। पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा अभी कुछ धार्मिक स्थलों पर प्रारंभ की जा रही है। यह सुविधा भविष्य में प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के लिए प्रारंभ होगी।

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री



## पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा संचालन आरंभ



इन स्थलों के लिए सेवा प्रारंभ

महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, पंचमढ़ी, खजुराहो, कान्हा, इंदौर, भोपाल

बुकिंग के लिए सम्पर्क करें -

8076807095, 8076819774, Website : [www.irctc.co.in](http://www.irctc.co.in), [www.serbaviation.in](http://www.serbaviation.in) R.O. No. D19159/24

मध्यप्रदेश शासन



# स्वाधीनता संग्राम के प्रखर और कर्मठ नेता थे पं. नारायणराव मेघावाले

सन् 1911 में पं. नारायणराव जी ने प्रथम बार धमतरी में गणेशोत्सव का आयोजन किया। वस्तुतः ये गणेशोत्सव राष्ट्रीय-जागरण के लिए वातावरण बनाने का कार्य था। गणेशोत्सव के कार्यक्रम में मुसलमानों से भी सहयोग प्राप्त किया जाता था। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम सिरमौर है। स्वाधीनता संग्राम में दिया इनका योगदान अतुलनीय और अद्भुत है। यही कारण है कि आज प्रदेश में यह प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अपने सम्पूर्ण जीवन में पं. नारायण जी किसानों के हितों के संरक्षण और स्वाधीनता की क्रांति की अलख जगाने में संघर्षरत रहे। राष्ट्र इनके योगदान और बलिदान को सदैव याद रखेगा।

## विजया पाठक

पं. नारायणराव मेघावाले (फड़नवीस) स्वाधीनता संग्राम की प्रथम पंक्ति के अत्यंत प्रखर और कर्मठ नेता थे। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम सिरमौर है। स्वाधीनता संग्राम में दिया इनका योगदान अतुलनीय और अद्भुत है। यही कारण है कि आज प्रदेश में यह प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अपने सम्पूर्ण जीवन में पं. नारायण जी किसानों के हितों के संरक्षण और स्वाधीनता की क्रांति की अलख जगाने में संघर्षरत रहे। राष्ट्र इनके योगदान और बलिदान को सदैव याद रखेगा।

वे सच्चे अर्थों में किसानों के हित-चिंतक थे। साहूकारों के शोषण से किसानों को बचाने के लिए उन्होंने पंचायती कोठियों का निर्माण करवाया।

मराठी भाषी होकर भी वे हिन्दी के पक्षधर थे। अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी पर उनका समान अधिकार था। छत्तीसगढ़ में वे



धारा प्रवाह भाषण देते थे। वे कट्टर वैष्णव तथा सात्विक विचारों के राजनीतिक संत थे। उन्होंने जीवन भर देश की स्वाधीनता के लिए कठोर परिश्रम किया। वे सच्चे अर्थों में कर्मवीर थे।

पं. नारायण राव फड़नवीस का जन्म 25 अक्टूबर 1883 को धमतरी नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम पं. विट्ठलराव तथा माता का नाम रुक्माबाई था। पं. नारायणराव जी सम्पन्न तथा यशस्वी परिवार से थे। धमतरी तहसील में उनके तीन गांव थे। मेघा, मुजगहन तथा माकरदोना। नारायणराव जी मेघावाले के नाम से ही अधिक विख्यात हुए।

सन् 1905 में नारायण जी ने सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके ऊपर लोकमान्य तिलक का प्रभाव था।

सन् 1911 में पं. नारायणराव जी ने प्रथम बार धमतरी में गणेशोत्सव का आयोजन किया। वस्तुतः ये गणेशोत्सव राष्ट्रीय-जागरण के लिए वातावरण बनाने का कार्य था। गणेशोत्सव के कार्यक्रम में मुसलमानों से भी सहयोग प्राप्त किया जाता था।

सन् 1915 में जब छोटे लाल बाबू ने धमतरी में वाचनालय की स्थापना की तो



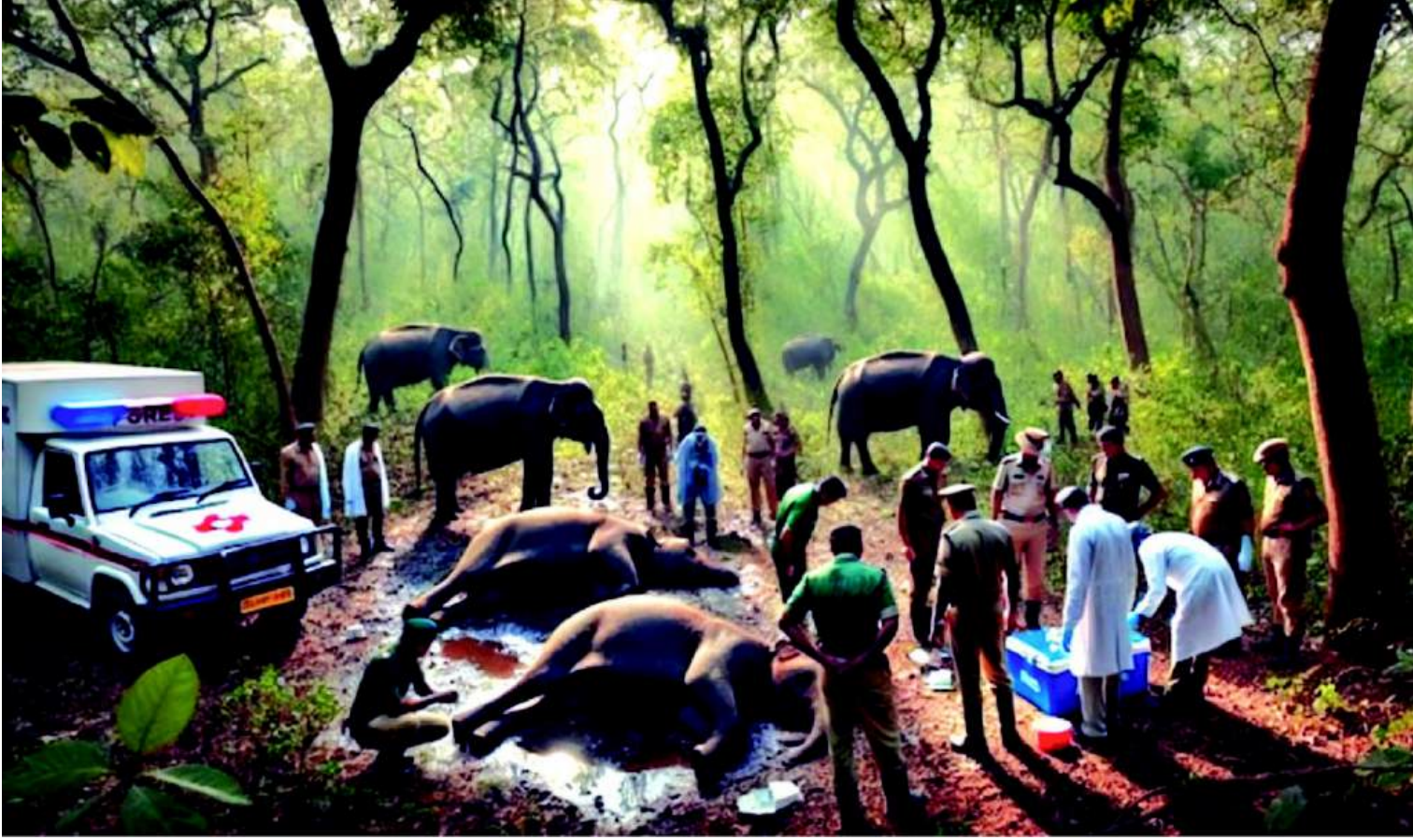
नारायणराव जी उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे इस पुस्तकालय के जीवन भर अध्यक्ष रहे।

सन् 1920 के अगस्त माह में छोटेलाल बाबू ने नेतृत्व में कण्डेल नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ। इस आंदोलन के प्रचार और प्रसार के लिए नारायणराव जी तथा पं. सुंदरलाल शर्मा ने गांव-गांव का दौरा किया। यह सत्याग्रह भारत का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। यह इन नेताओं के प्रभावशील नेतृत्व का ही परिणाम था कि कण्डेल ग्रामवासियों की सरकार द्वारा कुर्कशुदा मवेशियों की नीलामी में बोली बोलने वाला एक भी आदमी सामने नहीं आया। हर बाजार में बाजार के दिन जाकर अधिकारी चार माह तक प्रयास करते रहे

किन्तु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। आन्दोलन का विस्तार होता गया। अंत में निर्णय लिया गया कि आन्दोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंप दिया जाये। उनसे सम्पर्क करने के लिए पं. सुंदरलाल शर्मा को 2 दिसम्बर, 1920 को कलकत्ता भेजा गया। किन्तु गांधी जी के आगमन के पूर्व ही सरकारी अधिकारियों ने घुटने टेक दिए। गांधी जी आए और धमतरी भी गये। तब तक इस आंदोलन में विजय प्राप्त हो चुकी थी। गांधी जी ने असहयोग तथा सत्याग्रह की शक्ति को और बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर जन-मानस तैयार करने का उपदेश दिया।

1921 में मेघावाले जी धमतरी नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए

थे। सन् 1932 में नारायणराव जी के एक पुत्र केशवराव जी का आकस्मिक निधन हो गया। पुत्र के निधन से नारायणराव जी का हृदय टूट गया। धीरे-धीरे वे सार्वजनिक जीवन से विरक्त होने लगे। अपना सारा समय गांव में एकांत में व्यतीत करते। बाद में वे लम्बी तीर्थ-यात्रा पर निकल गये। वे रक्तचाप के शिकार हो गये थे। दिनांक 24 अक्टूबर 1938 को रायपुर में उनका निधन हो गया। रायपुर में शोकसभा आयोजित की गई, जिसे ठा. प्यारेलाल सिंह आदि नेताओं ने संबोधित किया। धमतरी निवासियों को जब नारायणराव जी के निधन का समाचार मिला तो वहां से तीन लारियों में वहां के नेता और नागरिक रायपुर आए। नारायणराव जी का अंतिम संस्कार रायपुर में ही हुआ।



# हाथी और मानव के बीच बढ़ा संघर्ष

## प्रमोद भार्गव

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों से हाथियों की असामयिक मौत की खबरें आना कोई नई बात नहीं है। नई बात इन हाथियों के मौत के कारण से जुड़ी है। इस बार एक सप्ताह के अंतराल में दस हाथियों की मौत हुई है और इस मौत का ठीकरा वनाधिकारियों ने संक्रमित कोदो-कुटकी की खेतों में खड़ी फसल को खाने पर फोड़ दिया। अकसर देखने में आया है कि उमरिया जिले के इस उद्यान में जब भी हाथी या बाघों की मौत होती है तो हाथियों

की मौत को जहर खिलाना और बाघों की मौत को आपसी संघर्ष में मरना बताकर वन विभाग अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। इन मौतों के बाद हाथियों का गुस्सा उद्यान से 10 किमी दूर देवरा गांव के ग्रामीणों पर टूटता दिखा। 13 हाथियों के इस झुंड से तीन हाथी अलग हो गए थे। इन हाथियों में से एक ने देवरा, ब्राहे और बांका ग्राम में पहुंचकर तीन लोगों पर हमला बोला। इनमें से दो की मौत हो गई और एक घायल है। इस मदांध हाथी को वनकर्मियों ने पकड़ लिया है। वनाधिकारी बता रहे हैं कि

यह हाथी उन्माद (मुस्थ) की अवस्था में पकड़ है। इस अवस्था का मतलब होता है कि हाथी प्रजनन काल से गुजर रहा है। इस अवधि में इसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ने लगता है और यह आक्रामक हो जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दस हाथियों के मामले को गंभीरता से लिया और निगरानी में लापरवाही के बरतने के चलते आभ्याराण्य के निदेशक गौरव चौधरी और प्रभारी सहायक वन संरक्षक अधिकारी फतेह सिंह को निलंबित कर दिया।

14 सदस्यीय चिकित्सकों के एक दल

ने हाथियों के शव-विच्छेदन में पाया कि हाथियों के पेट में संक्रमित कोदो-कुटकी पाया गया है। इसे हाथियों ने जंगल से सटे खेतों में खड़ी कोदो-कुटकी की फसल को खाया था। यह कोदो-कुटकी माइकोटोक्सिन (कवक विश) बन गया था। बारिश के बाद प्रतिकूल मौसम के चलते कोदो-कुटकी सहित कवक विश उत्पन्न हो जाता है। अतएव संक्रमित फसल के सेवन से पशुओं में संक्रमण हो जाता है। इस संक्रमण का समय रहते इलाज न हो पाए और यह बढ़ता जाए तो प्राणी की मौत हो जाती है। यह मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। अब वन-विभाग ने उद्यान की सीमा से सटे खेतों की फसल नष्ट करा दी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब ऐसी आशंका थी तो हाथियों को इन खेतों की फसल को चरने ही क्यों दिया? जबकि वर्तमान में प्रत्येक बड़े हाथी, बाघ एवं चीता के आरक्षित

**भारत सरकार ने हाथी को दुर्लभ प्राणी व राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा दी हुई है। इसलिए जंगलों में हाथियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।**

आवासीय वनों में कई-कई पशु-चिकित्सक तैनात हैं और निगरानी के लिए अनेक वन रक्षक तैनात रहते हैं। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना के पहले कोदो खाने से हाथियों की मौतें हुईं, और

ऐसी खबर नहीं आई? क्या हाथियों ने पहली बार यह फसल खाई थी? हालांकि संक्रमित भोजन के नमूने देश की अन्य प्रयोगशालाओं में भेजने के साथ सेंटर फोर सेलुलर एंड मालिक्यूलर बायोलॉजी, प्रयोगशाला हैदराबाद से भी परामर्श लिया जा रहा है। एसआईटी और एसटीएसएफ के दल भी सभी संभावित पहलुओं पर जांच करेंगे।

भारत सरकार ने हाथी को दुर्लभ प्राणी व राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा दी हुई है। इसलिए जंगलों में हाथियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। हालांकि हमारी सनातन संस्कृति में हाथी सह-जीवन का हिस्सा है। इसीलिए हाथी पाले और पूजे जाते हैं। असम के जंगलों में हाथी लकड़ी ढुलाई का काम करते हैं। सर्कस के खिलाड़ी और सड़कों पर





तमाशा दिखाने वाले मदारी इन्हें पढ़ा व सिखाकर अजूबे दिखाने का काम भी करते रहे हैं। साधु-संत और सेनाओं ने भी हाथियों का खूब उपयोग किया है। कई उद्यानों में पर्यटकों को हाथी की पीठ पर बिठाकर बाघ के दर्शन कराए जाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद अब ये केवल प्राणी उद्यानों और चिड़ियाघरों में ही सिमट गए हैं। बावजूद इन उद्यानों में इसकी हड्डियों और दातों के लिए खूब शिकार हो रहा है। हाथी के शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन व्यवहार में हाथी का शिकार करने वालों से लेकर आम लोग भी इस तरह के कानूनों की परवाह नहीं करते? कर्नाटक के जंगलों में कुख्यात तस्कर वीरप्पन ने इसके दांतों की तस्करी के लिए सैकड़ों हाथियों को मारा था। चीन हाथी दांत का सबसे बड़ा खरीददार है। जिन जंगलों के बीच में रेल पटरियां बिछी हैं, वहां ये रेलों की चपेट में आकर भी बड़ी संख्या में प्राण गंवाते रहते हैं।

मनुष्य के जंगली व्यवहार के विपरीत

हाथियों का भी मनुष्य के प्रति क्रूर आचरण देखने में आता है। जैसा कि 10 हाथियों की मौत के बाद इसी झुंड के एक हाथी ने तीन ग्रामीणों पर जानलेवा हमला बोला है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और कर्नाटक के जंगली हाथी अक्सर जंगल से भटककर

**कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में हाथियों ने इतना भयानक उत्पात मचाया था कि यहां 22 निर्दोष आदिवासियों की जान ले ली थी। कर्नाटक और बिहार में इन हाथियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या जोड़ लें तो ये हाथी दस-बारह साल के भीतर करीब सवा-सौ लोगों की जान ले चुके हैं।**

ग्रामीण इलाकों में उत्पात मचाते रहते हैं। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में हाथियों ने इतना भयानक उत्पात मचाया था कि यहां 22 निर्दोष आदिवासियों की जान ले ली थी। कर्नाटक और बिहार में इन हाथियों द्वारा मारे गए लोगों की संख्या जोड़ लें तो ये हाथी दस-बारह साल के भीतर करीब सवा-सौ लोगों की जान ले चुके हैं। शहडोल, रायगढ़, सरगुजा जिलों के दूर-दराज के गांवों में रहने वाले आदिवासियों के घरों में उतारी जाने वाली शराब को पीने की तड़प में भी हाथी गंध के सहारे आदिवासियों की झोंपड़ियों को तोड़ते हुए घुसते चले जाते हैं और जो भी सामने आता है उसे सूंड से पकड़ कर पटका और पेट पर भारी-भरकम पैर रख उसकी जीवन लीला खत्म कर देते हैं। इस तरह से इन मदांध हाथियों द्वारा हत्या का सिलसिला हर साल अनेक गांवों में देखने में आता रहता है।

पालतू हाथी भी कई बार गुस्से में आ जाते हैं। ये गुस्से में क्यों आते हैं, इसे



समझने के लिए इनके आचार, व्यवहार और प्रजनन संबंधी क्रियाओं व भावनाओं को समझना जरूरी है। हाथी मद की अवस्था में आने के बाद ही मदांध होकर अपना आपा खोता है। हाथियों की इस मनस्थिति के सिलसिले में प्रसिद्ध वन्य प्राणी विशेषज्ञ रमेश बेदी ने लिखा है कि जब हाथी प्रजनन की अवस्था में आता है तो वह समागम के लिए मादा को ढूंढता है। ऐसी अवस्था में पालतू नर हाथियों को लोगों के बीच नहीं ले जाना चाहिए। मद में आने से पूर्व हाथी संकेत भी देते हैं। हाथियों की आंखों से तेल जैसे तरल पदार्थ का रिसाव होने लगता है और उनके पैर पेशाब से गीले रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में महावतों को चाहिए कि वे हाथियों को भीड़ वाले इलाके से दूर बंदी अवस्था में ही रखें, क्योंकि अन्य मादा प्राणियों की तरह रजस्वला स्त्रियों से एस्ट्रोजन हार्मोन्स की महक उठती है और हाथी ऐसे में बेकाबू होकर उन्मादित हो उठते हैं। त्रिचूर, मैसूर और वाराणसी में ऐसे हालातों के चलते अनेक घटनाएं, घट चुकी हैं। ये प्राणी मनोविज्ञान की ऐसी ही

मनःस्थितियों से उपजी घटनाएं हैं। वैसे हाथियों के ऐसे व्यवहार को लेकर काफी नासमझी की स्थिति है, मगर समझदारी इसी में है कि धन के लालच में मद में आए हाथी को किसी उत्सव या समारोह में न ले जाया जाए। जिस हाथी ने तीन लोगों पर हमला बोला है, वह उन्माद की अवस्था में ही था।

**उत्पाती हाथियों को पकड़कर बीस साल पहले मध्यप्रदेश में**

**'ऑपरेशन खेदा' चलाया गया था। हालांकि पूर्ण वयस्क हो चुके हाथियों को पालतू बनाना एक चुनौती व जोखिम भरा काम है। हाथियों को बाल्यावस्था में ही आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। हाथी देखने में भले ही सीधा और भोला लगे पर आदमी की जान के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी हैं, उनमें एक हाथी है और दूसरा है भालू है।**

उत्पाती हाथियों को पकड़कर बीस साल पहले मध्यप्रदेश में 'ऑपरेशन खेदा' चलाया गया था। हालांकि पूर्ण वयस्क हो चुके हाथियों को पालतू बनाना एक चुनौती व जोखिम भरा काम है। हाथियों को बाल्यावस्था में ही आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। हाथी देखने में भले ही सीधा और भोला लगे पर आदमी की जान के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी हैं, उनमें एक हाथी है और दूसरा है भालू है। हाथी उत्तेजित हो जाए तो उसे संभालना मुश्किल होता है। फिलहाल इस तरह हाथी को पालतू बनाए जाने के उपाय बंद हैं। आखिर, जिस वन अमले पर अरबों रुपए का बजट सालभर में खर्च होता है, उसके पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई कारण उपाय क्यों नहीं है ? अतएव हाथियों की मौत हो या वे उत्पात मचाएं, मरना ग्रामीणों का ही होता है। इस मामले में भी सीधे-सीधे गरीब ग्रामीणों की फसलें उजाड़ दी गईं। जबकि सावधानी नहीं बरतने के लिए किसी पशु-चिकित्सक, वनाधिकारी या वन रक्षक को दोशी नहीं ठहराया गया ?



# आबादी के आंकड़ों की छिपी कहानी

**रघु ठाकुर**

पिछले कुछ दिनों से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थाओं के माध्यम से ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनसे लगता है कि देश में आबादी वृद्धि स्वयं मेव नियंत्रित हो चुकी है और अब आबादी वृद्धि कोई समस्या नहीं है। यह बात हमारे देश के बौद्धिक तत्वों में भी चल रही है जो इन अध्ययन संस्थाओं के अध्ययनों पर पूर्ण विश्वास करते हैं। वे यह पता लगाने का प्रयास नहीं करते हैं कि इन अध्ययनकर्ताओं ने किस माध्यम से अध्ययन किए हैं और कब किए हैं और क्या वास्तव में जमीन पर ऐसी स्थिति है? जिसकी चर्चा वह कर रहे हैं। अक्सर यह होता है कि देश के विभिन्न तबके अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार उनकी तथ्यात्मक जांच कराए बगैर आंकड़े

उद्धृत, प्रचारित और प्रसारित करने लगते हैं। भारतीय राजनीति के राजनीतिक समूह भी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को अपनी अपनी राजनीतिक आवश्यकता और सुविधा के अनुसार प्रचारित करते हैं और कई बार तो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन अध्ययन रपटों को अपना आधार बताते हैं। लगभग दो तीन दशक पहले गोपाल सिंह कमेटी की एक रपट आई थी, जिसने यह कहा था कि देश में मुस्लिम आबादी की वृद्धि तुलनात्मक रूप से गैर मुस्लिम या हिंदू आबादी की वृद्धि दर से कम है और इस रपट का काफी सार्वजनिक प्रयोग देश के गैर भाजपाई समूहों याने कांग्रेस, समाजवादी, मार्क्सवादी दलों ने किया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे अध्ययनकर्ताओं की रपट भी आई कि देश

में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तथा तुलनात्मक रूप से हिंदू आबादी घट रही है। इस समूह ने अपने अध्ययनकर्ताओं की रिपोर्ट को जोरशोर से प्रसारित किया और आम हिंदू मानस में यह प्रचारित करने का प्रयास किया की बहुत जल्दी देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यहां तक की इसी रपट के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक स्वर्गीय के पी सुदर्शन ने तो यह सार्वजनिक बयान दिया था कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मैं, नहीं जानता हूँ और मेरी जानकारी में कोई ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है कि जिसमें यह तत्व सामने आया हो कि स्वर्गीय सुदर्शन की अपील पर कितने हिंदुओं ने ज्यादा बच्चे पैदा किए या किसी अध्ययन में इस पर भी विश्वसनीय रपट नहीं आई कि

मुस्लिम भाइयों के स्व नियंत्रण से आबादी की वृद्धि में कितनी कमी आई या नियंत्रण हो सका।

हालांकि इन दोनों घटनाओं का यह तो असर हुआ कि परिवार नियोजन की योजनाएं और विभाग लगभग ठप जैसा हो गया। वैसे भी 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में, आपातकाल के दिनों में, परिवार नियोजन के नाम पर हुई ज्यादतियों ने एक अहम भूमिका निभाई और एक मुस्लिम मतदाता के हिस्से ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय संजय गांधी और कांग्रेस के लिए वोट नहीं दिया था। उस समय के समाचार पत्रों में यह सूचनाओं आई थी कि स्वर्गीय संजय गांधी परिवार नियोजन के कार्यक्रम को सरकार की शक्ति से लागू करने के पक्षधर थे और इसीलिए ज्यादतियां हुई थी तथा कांग्रेस का परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हुआ था। इन सूचनाओं का इतना राजनीतिक प्रभाव तो हुआ ही था कि 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनकर आई तो

**भारतीय राजनीति का आबादी संबंधी संवाद लगभग 1980 से लेकर 2000 तक बिल्कुल ही मुख्य संवाद के मुद्दों से हट गया। स्वर्गीय सुदर्शन जी के प्रभाव में यह भी हुआ कि जब मध्य प्रदेश में 2003 में भाजपा सरकार बनी और उस सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने तो उन्होंने दिग्विजय सिंह की सरकार के द्वारा उठाए गए आबादी नियंत्रण के एक तार्किक और वैधानिक कार्यक्रम को भी समाप्त कर दिया।**

उन्होंने आबादी नियंत्रण कार्यक्रम को सरकारी सूची से अघोषित रूप से लगभग हटा दिया था तथा जनता पार्टी की सरकार जिसमें तत्कालीन जनसंख्या और पृष्ठभूमि में आरएसएस शामिल थी, ने अपनी पूर्व भूमिका को कुछ बदला तथा परिवार नियोजन पर मौन साध लिया। कुल

मिलाकर भारतीय राजनीति का आबादी संबंधी संवाद लगभग 1980 से लेकर 2000 तक बिल्कुल ही मुख्य संवाद के मुद्दों से हट गया। स्वर्गीय सुदर्शन जी के प्रभाव में यह भी हुआ कि जब मध्य प्रदेश में 2003 में भाजपा सरकार बनी और उस सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने तो उन्होंने दिग्विजय सिंह की सरकार के द्वारा उठाए गए आबादी नियंत्रण के एक तार्किक और वैधानिक कार्यक्रम को भी समाप्त कर दिया। भले ही देश में आज श्री दिग्विजय सिंह की छवि मुस्लिम परस्त बनाई गई हो परंतु मैं आज भी उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने अपनी सरकार में स्थानीय संस्थाओं के लिए यह नियम बनाया था कि पंच, सरपंच आदि का चुनाव वही लोग लड़ सकेंगे जिनके अधिकतम दो बच्चे हों। उन्होंने इस कानून को विधानसभा से पारित भी कराया था और इस कानून को धर्म जाति या किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त रखा था। उस समय विधानसभा में भाजपा ने इसका





इसका समर्थन किया था और उसी भाजपा ने पूर्ण यू टर्न लेकर 2008 के बाद उसे समाप्त कर दिया था। भाजपा को भी नीतियों के मामले में अपनी तत्कालीन राजनीतिक जरूरतों के आधार पर उलट पलट करने का उत्कृष्ट कौशल हासिल है।

अभी पिछले दिनों में इलाहाबाद में एक पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम में गया था और वहां मैंने देश की आबादी वृद्धि की समस्या के प्रश्न के उत्तर में उल्लेखित किया था। मेरे एक बुद्धिजीवी मित्र जो की एक प्रोफेसर रहे हैं ने मुझे टोकते हुए हस्तक्षेप किया कि देश में आबादी की वृद्धि की दर उनके द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्थिर हो चुकी है और आबादी वृद्धि अब कोई समस्या नहीं है। हालांकि मैं उनके इस ज्ञान से सहमत नहीं हूँ। मैं अपने दिनांदिन जीवन और देश को जिस रूप में देख रहा हूँ उसमें मुझे आबादी वृद्धि तो दूर आबादी वृद्धि का विस्फोट नजर आता है। दुनिया के वैश्विक अध्ययन संस्थानों में आमतौर पर कॉरपोरेट फंडिंग होती है और वे अपने आप को एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन कहते हैं ने अब एक नई चर्चा शुरू की है जो आबादी की वृद्धि के लिए तर्क के पैर देती है। देश की सार्वजनिक स्मृति अक्सर कमजोर होती है और वह घटनाओं या सूचनाओं के मीडिया के मुख्य पृष्ठ या मुख्य खबर से हटते ही धीरे-धीरे अपने आप भुला दी जाती है। 2009 के आसपास जब स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे सत्ता प्रतिष्ठानों के केंद्र से यह चर्चा शुरू हुई थी कि भारत अब युवकों का देश बन गया है और दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है न केवल तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बल्कि लगभग सभी दलों के राजनेता मुझ जैसे को छोड़कर इस पर गौरवान्वित होते थे कि देश की यह एक बड़ी उपलब्धि है कि देश युवाओं का देश है। हालांकि मैं लगातार कहता और बोलता रहा कि इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है



और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो यह भी संकेत देती है कि 85 से 90 के बाद देश की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। अगर यह प्रसन्नता का कारण सही भी है तब भी दूसरे पक्ष महत्वपूर्ण हैं। तथ्य यह है कि अधिकांश युवा बेरोजगार हैं या अर्ध रोजगार में हैं। युवकों का एक बड़ा हिस्सा अपराधों

में लिप्त है और संस्कार तथा मूल्य विहीनता में जी रहा है। एक अच्छी खासी युवा आबादी नशे में डूबी है इसलिए युवाओं की संख्या गौरव की बात नहीं है बल्कि देश में एक ऐसे युवाओं की संख्या हो जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, देश और समाज के प्रति समर्पित हो, जीवन मूल्यों के प्रति संकल्पित हो, वह गौरव की बात हो सकती है। जिन वैश्विक शोध संस्थानों ने यह आंकड़े देकर उस समय देश को युवा आबादी का देश बनने का उत्सव मनवाया था अब वही कुछ दिनों से कह रहे हैं कि भारत बूढ़ा हो रहा है और युवा आबादी घट रही है। भारत सरकार ने यूथ इंडिया 2022 की रपट जारी की है कि देश की युवा आबादी जो अभी 47 प्रतिशत है वह घटकर 2036 तक 34.55 करोड़ हो जाएगी। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच के हैं और अगले 15 वर्षों में यह संख्या और कम होगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनपीएफ की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, के अनुसार 2011 में

**यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो यह भी संकेत देती है कि 85 से 90 के बाद देश की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। अगर यह प्रसन्नता का कारण सही भी है तब भी दूसरे पक्ष महत्वपूर्ण हैं। तथ्य यह है कि अधिकांश युवा बेरोजगार हैं या अर्ध रोजगार में हैं। युवकों का एक बड़ा हिस्सा अपराधों में लिप्त है और संस्कार तथा मूल्य विहीनता में जी रहा है।**

भारत की युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी जो अब बढ़कर 2023 में 29 साल हो गई है यानी बुजुर्गों की संख्या 2050 तक बढ़कर लगभग कुल आबादी की 20 प्रतिशत हो जाएगी। यूथ इंडिया भारत सरकार की रपट में यह भी कहा गया की 2011 में प्रजनन दर 2.4 प्रतिशत थी जो अब घटकर दो प्रतिशत हो गई है तथा मृत्यु दर जो 2011 में प्रति हजार 7.1 थी वह 2019 में घटकर 6 हो गई है। संभवत 2024 में यह घटकर चार या पांच के बीच हो जाएगी।

1950 के दशक में देश की आबादी की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत थी जो 2024 में घटकर 1 प्रतिशत हो गई है। नायडू के बारे में मेरी समझ पहले भी थी और आज भी है कि वह अमेरिका व पूंजीवादी दुनिया के आर्थिक एजेंट को लागू करने वाले सीईओ जैसे हैं, उसका प्रमाण तब भी मिला था जब देवगोडा देश के प्रधानमंत्री थे तथा नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। देश के प्रधानमंत्री ने एक राजनयिक शिष्टाचार के तहत उन्हें शाम को

अपने घर खाने का निमंत्रण दिया था पर उन्होंने उसे स्वीकार न कर पहले हैदराबाद जाकर चंद्रबाबू नायडू का निमंत्रण स्वीकार किया था। यह इस बात का प्रमाण है कि नायडू दुनिया के कारपोरेट और कारपोरेट सरकारों के सितारे रहे हैं। स्वाभाविक है कि वैश्विक दुनिया के अपने उद्देश्यों के लिए जारी किए गए आंकड़ों में उनका विश्वास कुछ ज्यादा ही है। उन्होंने बताया कि 1950 में जनसंख्या की वृद्धि दर 6 प्रतिशत थी यानी मान लो कि 1950 में देश की आबादी 36 करोड़ थी तो उसका 6 प्रतिशत लगभग



आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू बुजुर्ग आबादी को लेकर बहुत चिंतित हैं और उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी के प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए कहा कि लोग कम से कम दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करें, हम ऐसे दंपतियों को प्रोत्साहित करेंगे। राज्य सरकार शीघ्र ही ऐसा कानून लाएगी की दो या उससे अधिक बच्चे वाले ही चुनाव लड़ सकें। नायडू के इस बयान ने जहां एक तरफ पहले अधिकतम दो बच्चों की धारणा थी के स्थान पर अब न्यूनतम दो की नीति को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि

**यूथ इंडिया भारत सरकार की रपट में यह भी कहा गया की 2011 में प्रजनन दर 2.4 प्रतिशत थी जो अब घटकर दो प्रतिशत हो गई है तथा मृत्यु दर जो 2011 में प्रति हजार 7.1 थी वह 2019 में घटकर 6 हो गई है। संभवत 2024 में यह घटकर चार या पांच के बीच हो जाएगी।**

2.16 करोड़ हुआ। 1950 में मृत्यु दर प्रति हजार 12 थी यानी लगभग 44 लाख लोग देश में मृत्यु के शिकार होते थे। आबादी वृद्धि में से मौतों की संख्या को घटाकर याने जीवित आबादी वृद्धि बची लगभग 1.70 करोड़ और अगर उनका ही आंकड़ा माने तो अब प्रतिवर्ष की दर एक प्रतिशत, माने लगभग 1.5 करोड़ लोग और मृत्यु दर घट कर रह गई हजार पर छह की संख्या में। याने देश में मरने वालों की संख्या अब घटकर एक करोड़ प्रतिवर्ष। आबादी की वृद्धि संख्या और मृत्यु में कमी के बाद लगभग 2

करोड़ के आसपास नई आबादी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में आबादी पहले भी लगभग दो करोड़ प्रतिवर्ष के आसपास बढ़ रही थी अभी भी लगभग उतनी ही बढ़ रही है। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया है। कुल मिलाकर देश में औसत आबादी की वृद्धि प्रतिशत में भले ही कम हुई हो पर वास्तविक रूप में वह आज भी दो करोड़ के आसपास है याने लगभग यथावत है। दूसरा पक्ष यह भी है कि आंध्र प्रदेश अब विभाजित है उसका एक बड़ा हिस्सा तेलंगाना के रूप में नए प्रदेश में चला

का काम हो रहा है इसलिए वैसे ही युवकों के लिए रोजगार की संख्या काफी कम हो रही है और अगर युवकों की संख्या बढ़ जाए और वे केवल बेरोजगारी, भुखमरी, आत्महत्या या अपराधी होकर मरें तो ऐसी आबादी का भी कोई भला नहीं होगा। श्री नायडू को चाहिए कि वह अपने प्रदेश के किसानों की आत्महत्याओं को रोके, बेरोजगारों की आत्महत्याओं को रोके और जिंदा युवकों को बचाने का प्रयास करें।

विदेशी यूएनओ और एनजीओ के आंकड़ों के पीछे कई छिपे हुए वैश्विक हित

नया स्वरूप उससे भी भयावह है। अब उसे केवल, उन्नत तकनीक चाहिए जो हजारों लाखों का काम अकेले एक बटन से कर सके। पर रंगीन या गरीब दुनिया में, उसे खरीददार भी चाहिए, वरना विपुल पैदावार का क्या होगा? तो अब उसे, भारत, अफ्रीका जैसे देशों में खरीददारों की संख्या बढ़ाना है, तो फिर आबादी वृद्धि जरूरी है। शायद वृद्धों के बढ़ने का व जवानों के घटने का शोर इस रणनीति को त्रिभान्वित करने का एक हिस्सा है। रूस में यह ठीक हो सकता है क्योंकि बर्फीले प्रदेशों में प्राकृतिक रूप में जन्म दर



गया। इसलिए भी चंद्रबाबू नायडू का आबादी का आंकड़ा कुछ गड़बड़ आया हुआ लगता है। तीसरा पक्ष है कि चंद्रबाबू नायडू ज्यादा बच्चे पैदा करने के बजाय मृत्यु दर कम करने के प्रयास अपनी सरकार के माध्यम से करें तो यह विसंगति दूर होने लगेगी।

उन्हें वृद्धों की आबादी से भय है जोकि बहुत तार्किक नहीं है एक तो इसलिए कि आज मशीनीकरण और वैश्वीकरण के चलते एक-एक मशीन से कई हजार मजदूरों

होते हैं। वैश्विक पूंजीवाद निरंतर उन्नत और अति समर्थ तकनीक की ओर बढ़ रहा है। पहले यानी 18वीं सदी के पूंजीवाद में, एक मजदूर अपनी ताकत भर कमाकर, पूंजी के मालिक को देता था, जिसका कुछ हिस्सा उसे जिंदा रहने के लिए मजदूरी के रूप में वापस दिया जाता था ताकि वह जिंदा बना रहे और निरंतर काम करता रहे। वह इतना मजबूत भी नहीं हो कि काम ना करें, यानि इतना कमजोर भी ना रहे की काम करने के लायक भी ना रहे। पर अब पूंजीवाद का

बहुत कम रहती है। वैसे भी यूरोप अमेरिका में प्रति व्यक्तिक्षेत्रफल भारत की तुलना में ज्यादा है। आशा है देश में केंद्र की सरकार व सुबाई सरकारें इस षड्यंत्र को समझेंगी। जमीनी हकीकत यह है कि देश में आबादी का विस्फोट है और वह भयावह दृश्य पैदा कर रहा है। सरकार को जमीनी सत्य के आधार पर आबादी नियंत्रण नीति बनानी चाहिए जो धर्म जाति के आधार पर नहीं वरन सभी को साथ लेकर बने।

# भारत आज लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और डाटा के मजबूत स्तंभों पर खड़ा है



## किशन भवनानी, एडवोकेट

वैश्विक स्तर पर दुनियाँ देख रही है कि भारत के पड़ोसी देश अपनी-अपनी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं जैसे बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़क उठती है, पीएम के इस्तीफे पर का प्रूफ नहीं मिलने से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, पाकिस्तान के खैबर पशतून में बम धमाकों वह आंतरिक कलह,

तो श्रीलंका का संकट दुनिया देख चुकी है नेपाल में सत्ता परिवर्तन 50-50 पर हुआ है, परंतु भारतीय सरकार हैट्रिक 3.0 के आगाज़ पर वापसी कर रिकॉर्ड बनाया है, व तेज़ी से विज़न 2047 पर चल पड़ी है तथा इस यात्रा में सफलता के नए-नए अध्याय जोड़ते जा रहे हैं जिससे दुनिया दंग है, व भारतीय बौद्धिक क्षमता पर सटीक विश्वस्थ

हो चली है, क्योंकि दुनियाँ जानती है भारत आज मजबूत लोकतंत्र जनसांख्यिकी तंत्र, मांग और डाटा रूपी चार स्तंभों पर मज़बूती से खड़ी है। आज हम यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्मन चांसलर अपने लाव लश्कर के साथ 24 से 25 अक्टूबर 2024 तक भारतीय दौरे पर हैं तथा उन्होंने भारत की भर भर कर तारीफ़ की, क्योंकि भारत रू

स-यूक्रेन युद्ध शांति के भरपूर प्रयास कर रहा है तथा उन्होंने भारतीय टैलेंट श्रमिकों टेक्नीशियन की बौद्धिक क्षमता को पहचाना है व वीजा अब 20 से बढ़कर 90 हजार लोगों के लिए खोल दी है इससे उनके प्रभावित होने का अंदाजा लगाया जा सकता है, वहीं सम्मेलन में करीब 27 समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत में 12 वर्षों बाद 18 वाँ एशिया प्रशांत जर्मन कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर 2024 का आगाज़ जर्मन की रणनीति फोकस ऑन इंडिया का अभिनंदन करते हैं।

बात अगर हम 18 वें एशियाई प्रशांत कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर 2024 की करें तो, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय पीएम और जर्मनी के चांसलर ने शिरकत की। पीएम ने भारतीय आकांक्षाओं, विकसित भारत का रोडमैप और तकनीक और स्किल की बदौलत दुनियाँ को भरोसा दिलाया कि भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में भारत सक्षम है। 12 साल बाद भारत एशिया पैसिफिक क कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस की मेजबानी कर रहा है, पीएम ने कहा कि एक ओर सीईओ फोरम की मीटिंग चल रही है और दूसरी ओर दोनों देशों की नौसेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं, यह दर्शाता है कि हर स्तर पर भारत और जर्मनी के संबंध मजबूत हो रहे हैं देखें। पीएम ने जर्मन कंपनियों को देश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई स्थान नहीं है और देश की विकास गाथा में शामिल होने का यह सही समय है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत की मेक इन इंडिया पहल में शामिल होने और मेक फॉर द वर्ल्ड में शामिल होने का यह सही समय है। उन्होंने यह भी कहा कि



जर्मनी ने भारत की कुशल जनशक्ति में जो विश्वास व्यक्त किया है, वह अद्भुत है क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र ने कुशल भारतीय कार्यबल के लिए वीजा को 20 से बढ़ाकर 90 हजार करने का निर्णय लिया है, यह जर्मनी के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का रोडमैप तैयार किया है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने भारत पर ध्यान दस्तावेज़

जारी किया है। उन्होंने कहा, भारत की विकास गाथा में शामिल होने का यह सही समय है। भारत वैश्विक व्यापार और विनिर्माण केंद्र बन रहा है, उन्होंने कहा कि आज भारत लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और डेटा के मजबूत स्तंभों पर खड़ा है, भारत सड़कों और बंदरगाहों में रिकार्ड निवेश कर रहा है और इंडो-पाक रीजन दुनियाँ के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहा, भारत और जर्मनी के बीच





सातवें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन हुआ है। इसके अलावा व्यापार और सामरिक साझेदारी के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा महत्वपूर्ण रही। पीएम ने जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया रणनीति के लिए अभिनंदन किया और कहा कि इसमें विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच साझेदारी को व्यापक तरीके से आधुनिक बनाने और उंचा उठाने का ब्लू प्रिंट है।

बात अगर हम जर्मनी चांसलर द्वारा कार्यक्रम में संबोधन करने की करें तो, उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि हमें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। वैश्वीकरण सभी देशों की सफ लता की कहानी रही है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई देश इसके उदाहरण हैं। उन्होंने आगे कहा, 21वीं सदी की दुनियाँ कुछ ऐसी है, जहां हमें प्रगति के लिए काम करना है। बहुध्रुवीय दुनियाँ में कोई वैश्विक पुलिसकर्मी नहीं, कोई नियम, संस्थान नहीं। हममें से प्रत्येक को इसकी रक्षा करने के लिए बुलाया गया है। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सफल होता है तो इसका परिणाम यूरोपीय सीमाओं से परे होगा। इससे वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। मध्य-पूर्व में भी तनाव जारी है।

कोरियाई प्रायद्वीप दक्षिण-पूर्वी चीन सागर सभी युद्ध बिंदु पर हैं। आगे कहा, आज हमारे विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह भारतीयों का है। पिछले वर्ष ही जर्मनी में काम करने वाले भारतीयों की संख्या में 23 हजार की वृद्धि हुई। यह प्रतिभा हमारे श्रम बाजार में स्वागत योग्य है। उन्होंने बताया कि जर्मनी अपनी वीजा प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कर रहा है। प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। आईजीसी से पहले जर्मन व्यवसायों की एक बैठक को

**हमें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। वैश्वीकरण सभी देशों की सफ लता की कहानी रही है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई देश इसके उदाहरण हैं। उन्होंने आगे कहा, 21वीं सदी की दुनियाँ कुछ ऐसी है, जहां हमें प्रगति के लिए काम करना है।**

संबोधित करते हुए चांसलर ने भारत के बारे में कई सकारात्मक बातें कहीं, भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और दुनियाँ के सबसे गतिशील प्रांत एशिया प्रशांत का केंद्र है। हालांकि चांसलर ने व्यापार फोरम में बोलते हुए अनियमित आप्रवासन के बारे में चेताया और कहा कि जर्मनी कुशल कामगारों का स्वागत करता है, लेकिन किसे आने देना है और किसे नहीं इसका फैसला वह ही करेगा। तकनीक, कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ उर्जा से लेकर खुफि या जानकारी साझा करना और कानूनी मामलों में सहायता जैसे क्षेत्रों में सहयोग कार्यक्रमों की घोषणा की गई। मुक्त व्यापार के मोर्चे पर शॉल्ट्स ने कुछ छिपे हुए संदेश भी देने की कोशिश की, उन्होंने संरक्षणवाद का स्पष्ट रूप से विरोध किया और कहा कि विश्व व्यापार संगठन की बनाई व्यवस्था को मानना चाहिए और तरह-तरह के शुल्क लगाने से बचना चाहिए। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुफ्त व्यापार संधि (एफटीए) कराने की जर्मनी की कोशिशों का भी जिक्र किया और कहा कि अगर दोनों देश इस पर मिलकर काम करें, तो यह सालों की जगह कुछ ही महीनों में हो जाएगा। एफटीए पर अलग से भी दोनों देशों के बयान आए, जिनसे संकेत मिलता है कि अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है। जर्मनी के वाईस चांसलर और आर्थिक मामलों के मंत्री ने कहा कि एफटीए पर चर्चाओं में कृषि क्षेत्र एक मुश्किल विषय बना हुआ है। भारत के व्यापार मंत्री ने भी कहा कि ईयू के लिए अपना डेयरी बाजार नहीं खोलेगा और अगर इस पर जोर दिया गया, तो एफटीए होना मुश्किल है। 2022 में दोनों ही पक्षों ने 2023 तक एफटीए को संपन्न करने की बात की थी, लेकिन यह अभी तक हो नहीं पाया है।

# महाराष्ट्र और झारखंड के विस चुनाव में दांव पर लगी पार्टियों की साख उपचुनावों में भी लग रही जोर आजमाईस



## समता पाठक

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के आम चुनाव और 14 राज्यों की कुल 47 असेंबली व दो राज्यों की दो सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है। चुनाव में प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव जीतने की जुगत में लगी हैं। खासकर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में हैं। पार्टी के दिग्गज चुनाव प्रचार में हाथ आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्रो मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी जैसे स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला।

यह भी सच है कि हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस पर बेहतर प्रदर्शन दबाव काफी बढ़

**हरियाणा में कांग्रेस की  
करारी हार के बाद  
इंडिया गठबंधन,  
खासकर कांग्रेस पर  
बेहतर प्रदर्शन दबाव  
काफी बढ़ गया है।**

गया है। इंडिया गठबंधन के लिए ये चुनाव इसलिए अहम हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उसे महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, जबकि झारखंड में कांग्रेस-जेएमएम महागठबंधन को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना है।

महाराष्ट्र और झारखंड में मुफ्त बिजली, कर्ज माफी और महिलाओं को नकद लाभ जैसे चुनावी वादों से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ने की आशंका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन लोकलुभावन योजनाओं से राज्यों की माली हालत बिगड़ सकती है और विकास कार्यों पर खर्च कम हो सकता है। लड़की बहिन योजना,



किसानों की कर्ज माफी, कम बिजली बिल, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त गैस सिलिंडर जैसे चुनावी वादे महाराष्ट्र और झारखंड में गूँज रहे हैं। इनकी धमक आने वाले दिनों में इनके सरकारी खजाने को सहनी पड़ सकती है। फ्री बीज या रेवडियों की परिभाषा भले ही तय न की

जा सकी हो, ऐसे कदमों से राज्यों की माली हालत पर असर पड़ता ही है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह देखा जा चुका है। महाराष्ट्र में जिस लड़की बहिन योजना के तहत विपक्षी गठबंधन मौजूदा 1500 रुपये के बजाय 2000 रुपये महीना और

सत्तारूढ़ गठबंधन 2100 रुपये महीना देने के वादे कर रहे हैं, उसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर शुरू किया गया था। इस स्कीम ने बीजेपी को चुनावी फायदा तो दिया, लेकिन ऐसे चुनावी वादों का नतीजा यह हुआ कि पिछले वित्त वर्ष में एमपी को जमकर उधार लेना पड़ा





## उपचुनाव भी हैं अहम

इन दोनों राज्यों के साथ-साथ असेंबली व लोकसभा के चुनाव भी विपक्ष के लिए अहम हैं। केरल की वायनाड सीट कांग्रेस के खाते की है, यहां से राहुल गांधी चुनाव जीते थे, लेकिन वायनाड के साथ ही रायबरेली से जीत के बाद उन्होंने वायनाड की सीट खाली कर दी। अब उनकी जगह उनकी बहन प्रियंका यहां से चुनाव लड़ रही हैं। जबकि नांदेड की सीट कांग्रेस के वसंतराव चव्हाण के निधन के चलते खाली हुई। इस तरह से कांग्रेस के लिए इन दोनों सीटों पर जीतना बहुत जरूरी है, ताकि वह लोकसभा में अपने नंबरों को बनाए रख सके।



उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मझवां, खैर, मीरापुर, सीसामउ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामउ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई हैं। सीसामउ से इरफन सोलंकी के सजायाफता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। यूपी से सांसद बने 9 विधायकों ने 10 से 14 जून के बीच इस्तीफा दिया था। इस हिसाब से 14 दिसंबर के पहले ये सीटें भरी जानी चाहिए, लेकिन इरफन सोलंकी की सीसामउ सीट 7 जून को ही रिक्तघोषित की गई थी। इसलिए, यह 7 दिसंबर के पहले भरी जानी है। इसलिए नवंबर में चुनाव करवाने ही होंगे। 2027 में प्रस्तावित यूपी के विधानसभा चुनाव के लगभग सवा दो साल पहले होने वाले उपचुनाव को सियासी दल सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उपचुनाव वाली सीटें वेस्ट, सेंट्रल, अवध, पूर्वांचल सहित प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए नतीजे संभावनाओं के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। सबसे अहम बुधनी सीट है। यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है। वहीं राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें चार सीटों पर भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं तीन सीटें ऐसी हैं, जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला होना है। बिहार में 4 सीटें बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में उपचुनाव है। परिवारवाद से कोई भी सीट नहीं बच रही है। बेलागंज में आरजेडी के सांसद सुरेन्द्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह यादव को टिकट मिला है। इमामगंज में हम पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है।

सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार और पंजाब की 4-4, कर्नाटक की 3, केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम की 2-2, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ की 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

और उसका कुल कर्ज 4 लाख 18 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया और इस साल

94000 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज लेना पड़ सकता है।

झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरण में मतदान होंगे जबकि महाराष्ट्र में 20



नवंबर को वोटिंग होगी। विधानसभा के साथ बिहार यूपी समेत 15 राज्यों में उपचुनावों की भी तिथि जारी की गई। चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।

**झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा की तिथियां जारी**  
**महाराष्ट्र में किसका पलड़ा भारी ?**  
महाराष्ट्र का चुनाव इंडिया गठबंधन

यानी महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा अहम हैं। दरअसल, जिस तरह से उद्धव ठाकरे नीत अघाड़ी सरकार गिरी थी, उसे देखते हुए आरोप लगाया गया था कि बीजेपी

## झारखंड में 'इंडिया' देगा 10 लाख नौकरी और रोजगार

झारखंड में इंडिया ब्लाक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल हैं। इंडिया ब्लाक ने साझा घोषणापत्र जारी किया है। इंडिया ब्लाक ने वादा किया है कि दोबारा उसकी सरकार बनी तो रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। झारखंड के 10 लाख युवक और युवतियों को नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 लाख रूपए तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। पिछली बार भी इंडिया ब्लाक की अग्रणी पार्टी जेएमएम ने रोजगार का वादा किया था। रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी बात थी। वादे के मुताबिक युवाओं को न नौकरी मिल पाई और बेरोजगारी भत्ता ही मिला। इसे लेकर एनडीए की पार्टियां लगातार हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करती रही हैं। उनकी इस विफलता को वादाखिलाफी बता कर भाजपा ने चुनाव में आक्रामक रूख भी अख्तियार किया है।



ने शिवसेना में टूट करकर वहां सरकार बना ली। अपनी पार्टी में टूट के बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में वहां महायुति की सरकार बना ली। शिवसेना के बाद शरद पवार की एनसीपी में भी टूट देखी गई।

अघाड़ी इसे मोदी सरकार नीत केंद्र सरकार द्वारा गैर बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के तौर देखती रही है। 2019 के असेंबली चुनावों में 288 असेंबली सीटों में से बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, कांग्रेस को 44 व एनसीपी को 54 सीटें

मिली थीं। वहां शिवसेना व बीजेपी में चुनाव बाद समझौता न होने के चलते सरकार नहीं बनी, तब एनसीपी व कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन देकर साथ में सरकार बनाई। उस समय एनसीपी सुप्रिमो शरद पवार ने अहम भूमिका निभाते हुए कांग्रेस व



# महाराष्ट्र में भाजपा 25 लाख नौकरियां देगी

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति और महा विकास अघाड़ी ने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं। दोनों के घोषणापत्र में दूसरे आकर्षक और लोकलुभावन वादों के अलावा रोजगारी और नौकरी पर खास फोकस है। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति ने 25 लाख नौकरियों के अवसर सृजित करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें पांच साल में 10 लाख नए उद्यमी तैयार करने की बात है। इसके साथ ही भाजपा ने 10 लाख छात्रों को हर महीने 10 हजार



रूपए ट्यूशन फ्री देने का भी वादा किया है। दूसरी ओर महा विकास अघाड़ी ने सरकारी नौकरियों में ढाई लाख रिक्त पद भरने की गारंटी दी है। कांट्रैक्ट पर नियुक्तियों की परंपरा एमवीए बंद करेगा। सारी नियुक्तियां महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के जरिए होंगी। बेरोजगारों को हर महीने चार हजार रूपए की आर्थिक सहायता देने की गारंटी भी महा विकास अघाड़ी ने दी है।

शिवसेना को साथ लाने का काम किया। तमाम विरोधाभास के बाद महाविकास अघाड़ी के तीनों अहम घटक अभी भी साथ हैं। देखना होगा कि अघाड़ी लोकसभा का प्रदर्शन यहां दोहरा पाती हैं या नहीं।

## महाराष्ट्र का बजट झेल पाएगा चुनावी वादों का बोझ ?

महाराष्ट्र का हाल यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग की योजनाओं में जहां 4677 करोड़ रु पये का आवंटन किया गया था, वहीं केवल लड़की बहिन योजना पर सालाना 46000 करोड़ रु पये खर्च होने हैं, वह भी 1500 रु पये महीने के आधार पर। राज्य की माली हालत यह है कि पिछले वित्त वर्ष के रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुताबिक इसका राजकोषीय घाटा इसके GDP के 2.8 प्रतिशत पर था और मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में कहा गया था कि यह 2.6 प्रतिशत रहेगा।

**झारखंड में भी पार्टियां लगा रही जोर**  
झारखंड में इंडिया गठबंधन हर हालत में

अपनी सरकार बचाने के लिए जोर लगा रहा है। दरअसल, हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पांच साल की एंटी इनकंबेंसी की है। सोरेन सरकार में कथित भ्रष्टाचार व आदिवासी बहुल इलाकों में तेजी से बदलती आबादी की तस्वीर व धर्मांतरण को लेकर बीजेपी लगातार सोरेन सरकार व जेएमएम पर हमलावर है। यहां तक कि खुद सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जेल हो कर आए हैं। ऐसे में बीजेपी इन्हें बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर सोरेन व जेएमएम लोगों के बीच जाकर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, व लेफ्ट सीपीएमएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पिछले चुनाव में यहां जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन को 81 में से 47 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी को महज 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। यहां तक

कि तब बीजेपी नेता व तत्कालीन सीएम रघुवर दास तक चुनाव हार गए थे।

## झारखंड में भी गड़बड़ा सकता है पूरा बजट

उधर, झारखंड में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का जो बजट पारित किया गया था, उसमें पहले ही कृषि कर्ज माफी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जा चुकी है। 2023-24 के रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुताबिक फिस्कल डेफिसिट राज्य के जीडीपी के 2.7 प्रतिशत पर था, जिसके अब 2.02 प्रतिशत होने का अनुमान दिया गया। माइनिंग से होने वाली आमदनी के सहारे झारखंड 2016-17 से रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में है। वित्त वर्ष 2024 में झारखंड ने 4800 करोड़ रुपये सब्सिडी पर खर्च किए थे। लेकिन जिस तरह हर गरीब महिला को 2100 रुपये से लेकर 2500 रुपये महीने तक देने जैसे वादे किए गए हैं, उनको पूरा करने की बारी आई तो झारखंड का रेवेन्यू सरप्लस स्टेटस खतरे में पड़ सकता है।

# How many economists have seen the inside of a factory?

## Anil Varghese

Economist Jean Drèze has seen up close far too often governments failing the poor in rural India. As Donald Trump is re-elected president of the United States and Narendra Modi serves his third term in India both of whom scapegoat minorities for votes, Drèze, in this email interview with FORWARD Press, talks about an inward-looking academia, Brahmanism and white supremacy.

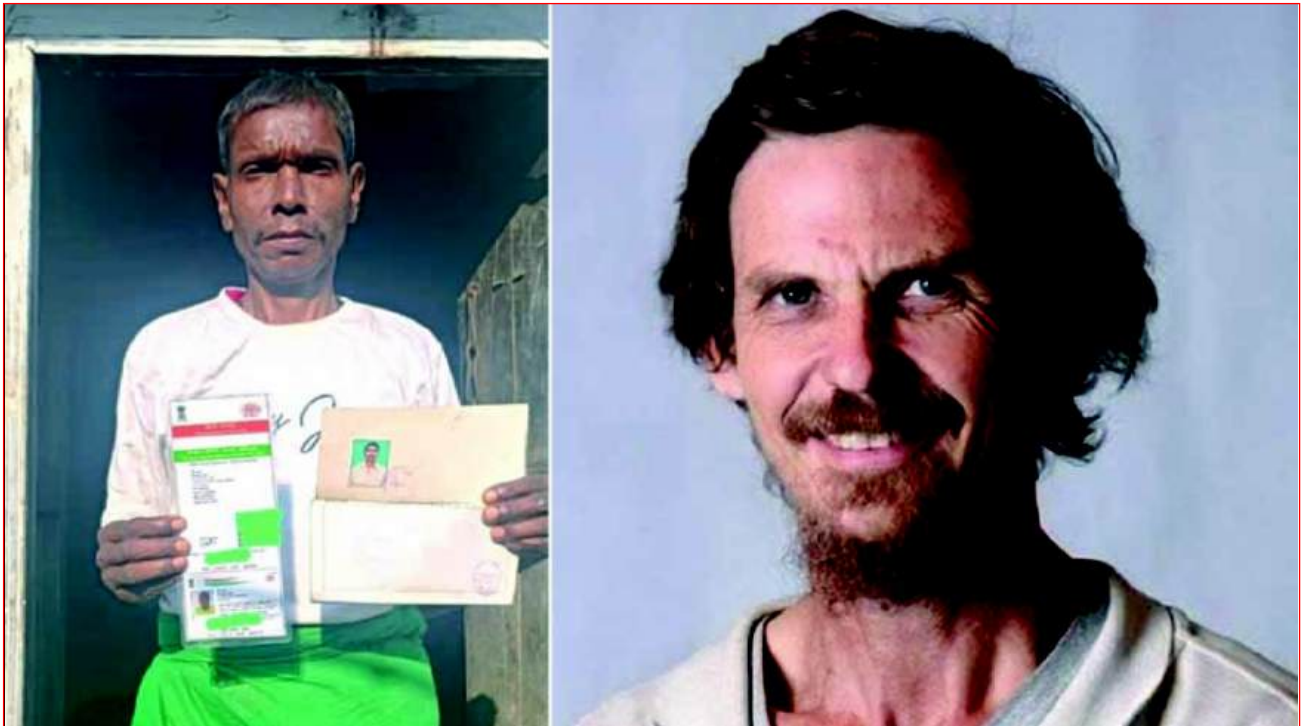
Academia in India and the US share close ties, with many Indian scholars having been trained in America and Americans coming to India for research, especially in the field of social sciences. How has academia played its part in the making of politics in both these countries?

In India at least, I don't think that academia has had much influence on politics, certainly not electoral politics. Academia tends to be inward-looking.

Student politics, however, often have a larger influence, as happened with the JP movement in the mid-1970s or the campus agitations in the US this year. Alas, the current political climate in India is hostile to student politics, or any form of dissent for that matter.

**Has higher education served to create a political elite and a media that is dissociated from the masses?**

The entire education system in India has an elitist bias. It is providing



world-class education for the privileged and ramshackle schools to marginalized communities. This layered system is a good deal for the privileged classes, that is why it is so resistant to change. It leads to a similar elitist bias in white-collar institutions such as the media, the judiciary and the administration. The political class is a little more diverse and better connected with the masses. But it is also privileged in its own way and not necessarily more committed to the interests of the underprivileged than the intellectual elite, except under pressure.

**How can higher education be made more relevant for the times we live in today?**

Universities developed as a kind of cocoon where a privileged minority was able to devote itself to intellectual



work with the benefit of exclusive libraries. Today, the library that most people have on their phone is vastly larger than most university libraries. The channels and methods of communication have also exploded.

The butterfly of knowledge has left its cocoon and is flying all over the place. I believe that universities still have a role, but they should try to reconnect with the living world instead of staying away from it. That will make them



more relevant, too.

**Would grounded economists help in bringing about good governance? Is there a lack of such economists in India today?**

I think that it would be a good thing for more economists to have practical experience of the economy. How many of them have seen the inside of a factory? Some do have experience of the banking sector, finance ministry or corporate boards. This can be useful, but it also reinforces the privileged mindset that we tend to acquire in exclusive educational institutions. Lack of practical experience may not be an issue if you want to prove theorems or crunch data, but it is essential for economists who wish to contribute to public policy. And even crunching data, quite often, benefits from an understanding of what lies behind the numbers.

**Have caste (India) and race (US)**



**played a role in the creation of the elite?**

Indeed, the caste system creates a permanent position at the top for a small minority. Today, this monopoly is being threatened to some extent by democratic institutions and the modern economy. This is one reason why the Hindutva movement is so

popular among the upper castes: it upholds a Brahmanical worldview that places them at the top. It is possible that something similar is happening in the US. A section of the white population resents having to share space with other races, so it throws its weight behind white supremacists. Remember, the





acceptance of Black people as equal citizens is very recent in the US. Of course, white supremacists are just a minority of Trump's supporters, just as Hindu nationalists are a minority of Modi's supporters. But both are powerful factions.

**Do educated liberals in India and the US suffer from a sense of entitlement by virtue of the caste and race they come from?**

I think that privileged people everywhere usually strive to defend their privileges. There are various ways of doing this. One is to hide your privileges, for instance by calling yourself "middle class" when you actually belong to the top income decile. Another is to claim that your privileges are due to hard work,

without acknowledging that your famished domestic help works even harder. A third is to try and keep the underprivileged in their place, for instance by inciting them against a powerless minority. Here again, there is a possible parallel between India and the US, with Muslims and illegal immigrants as the respective scapegoat minorities. No one is bound to fall into these traps, but it takes some work to avoid them.

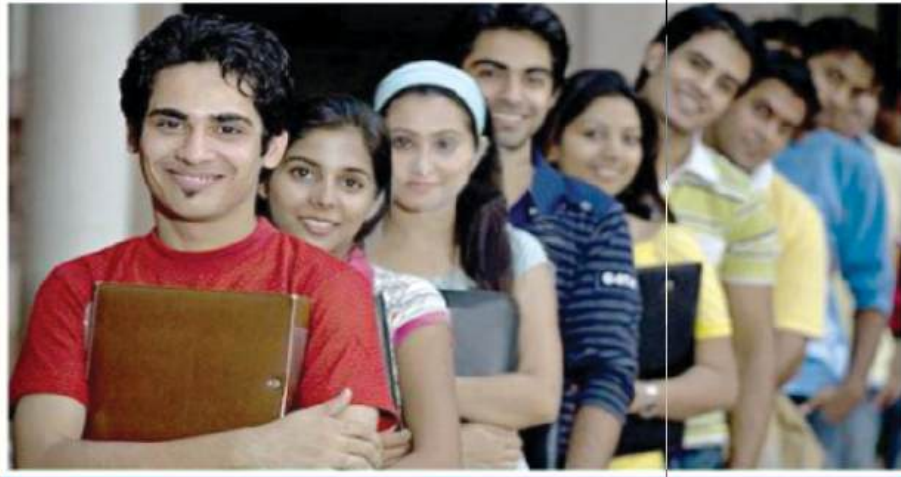
**Walking through the villages of Jharkhand and meeting poor Adivasis struggling to access their own bank accounts due to KYC issues, what are the thoughts that cross your mind concerning the ruling classes?**

The dominant thought or rather

feeling is dismay and anger at the sight of poor people being treated like shit. Their bank accounts are frozen at the drop of a hat. The system is blind to the ordeals they face with seemingly simple tasks such as ensuring that their name is spelt in the same way in their Aadhaar card and bank account. Assistance facilities are virtually non-existent. No one is accountable for errors, delays or violations of guidelines. Consent is a euphemism for coercion. The norms are basically designed for privileged people who have polished documents and digital skills. The rest are advised to improve their "financial literacy", as bank managers like to put it.



# जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल



जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

**: विषय :**

**मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)**

## प्रवेश प्रारंभ

**संपर्क सूत्र**

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.  
संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.